शर्मा हार्डওৱেৰ
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित
राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 11 | अंक : 232 | गुवाहाटी | मंगलवार, 25 मार्च, 2025 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

पीएम से मिले पीयूष-जयशंकर यूएस ट्रेड टैरिफ को लेकर हुई चर्चा पेज 2
उद्योग मंत्री बिमल बोरा ने इन्वेस्ट इंडिया के उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय का... पेज 3
किसान नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर फूंका पंजाब सरकार का पुतला पेज 5
नानजिंग में वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप का समापन डेविन चार्लटन... पेज 7

असम विस में हंगामा, कांग्रेस विधायकों की धक्का-मुक्की में डिप्टी स्पीकर घायल

विपक्ष ने भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा, काले कपड़े पहन किया प्रदर्शन

गुवाहाटी। असम विधानसभा में आज उस समय अफरा-तफरी मच गई जब आरोप त्रगे कि उपसभापति नुमाल मोमिन पर सदन के बाहर कांग्रेस विधायकों ने हमला किया। इस घटना के कारण सत्र स्थगित करना पड़ा और राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया। सत्तारूढ़ पार्टी ने कांग्रेस के रूपोही विधायक नूरुल हुदा पर उपसभापति नुमाल मोमिन के साथ हाथापाई करने का आरोप लगाया है, जिससे उनके बाएं हाथ में चोट लग गई, जिसके कारण सत्र स्थगित करना पड़ा। इस बीच, विपक्षी नेताओं का दावा है कि राजनीतिक लाभ के लिए इस घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के दौरान हंगामा तब हुआ जब कांग्रेस विधायक नूरुल हुदा कथित तौर पर डिप्टी स्पीकर नुमाल मोमिन की ओर बढ़े और उनके साथ हाथापाई की। मोमिन के बाएं हाथ में चोट लगी है, जो बाद में पट्टी बांधे हुए दिखाई दे रही थी। डिप्टी स्पीकर नुमाल मोमिन ने घटना का वर्णन करते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक नूरुल हुदा और वाजेद अली चोंधरी को काले कपड़े पहनकर विधानसभा में आने से रोकते समय धक्का-मुक्की और खींचतान के दौरान मुझे चोट लग गई। मैं 9 साल से विधायक हूं और 4 साल तक डिप्टी स्पीकर के पद पर रहा हूं, लेकिन ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था। कांग्रेस विधायकों ने भाजपा विधायक रूपज्योति कुर्मी के खिलाफ विरोध जताने के लिए विधानसभा में काली पोशाक पहनी। विपक्ष ने कुर्मी पर पिछले सप्ताह सदन के अंदर कांग्रेस विधायकों को गाली देने और उन पर शारीरिक हमला करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। काली पोशाक पहनकर प्रदर्शन का उद्देश्य सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक के असंसदीय व्यवहार के खिलाफ अपनी शिकायत को उजागर करना था। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि उन्हें नुमाल मोमिन का एक व्हाट्सएप संदेश मिला है जिसमें आरोप लगाया गया है -शेष पृष्ठ दो पर

गौ हमारी मां हैं, उनकी रक्षा करना हमारा धर्म : मुख्यमंत्री

गुवाहाटी (हि.स.)। असम विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर गो-तस्करी को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि गौ हमारी मां हैं, उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस ने गौ-तस्करी के सिंडिकेट के पैसे से चुनाव लड़ा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ 77 गौ-तस्करों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि हमारी सरकार ने पिछले चार वर्षों में चार हजार से अधिक गौ-तस्करों को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वह कांग्रेस में थे, तब उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग सौंपा गया था और उन्होंने इन विभागों में क्रांति लाई। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि तत्कालीन सरकार में जानबूझकर मुझे वन विभाग से दूर रखा गया, क्योंकि एक आंतरिक समूह वहां संगठित तरीके से शिकार का सिंडिकेट चला रहा था। उन्होंने असम में सुपारी सिंडिकेट को लेकर भी बड़े एलान किए। उन्होंने कहा -शेष पृष्ठ दो पर

राज्य में सुपारी उद्योग स्थापित किया जा सकता है : विस में सीएम

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने राज्य में सुपारी उद्योग स्थापित करने की योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने यह बयान सोमवार को विधानसभा में दिया। वर्तमान सरकार ने राज्य में संस्थाओं और विभागों की प्रचलित प्रणालियों में किस प्रकार परिवर्तन लाने का काम किया है, इस बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने सदन से पूछा कि राज्य में सुपारी उद्योग क्यों नहीं स्थापित किया जा सका। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि कई विधायकों ने मुझसे संपर्क किया है और पूछा है कि मैं असम की सुपारी को दूसरे राज्यों में जाने की अनुमति क्यों नहीं देता। वे अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे कदमों से किसानों और खेती करने वालों पर नकारात्मक असर पड़ता है। मेरा सवाल यह है कि हम असम में ही सुपारी उद्योग क्यों नहीं लगा सकते? इसी सुर में शर्मा ने कहा कि दो उद्योगपतियों ने असम में सुपारी उद्योग स्थापित करने की मंशा जताई है। -शेष पृष्ठ दो पर

door graph
Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

असम विस ने वित्त वर्ष 2026 के लिए राज्य बजट पारित किया

गुवाहाटी। असम विधानसभा ने सोमवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2.63 लाख करोड़ रुपए का राज्य बजट पारित किया। स्पीकर विश्वजीत दैमारी ने कहा कि असम विनेउग विधेयक, 2025 के पारित होने के साथ ही अगले वित्त वर्ष के लिए राज्य का बजट मंजूरी दे दी गई। वित्त मंत्री अजंता नेउग ने 10 मार्च को राज्य का बजट पेश किया था, जिसमें लोगों, खासकर युवाओं और चाय बागान श्रमिकों के लिए कई नकद प्रोत्साहन और अगले साल विधानसभा चुनावों से पहले वेतनभोगी वर्ग को कर छूट की घोषणा की गई थी। 620.27 करोड़ रुपए के घाटे -शेष पृष्ठ दो पर

बार एसोसिएशन ने राज्य में पूर्वोत्तर की सुप्रीम कोर्ट बेंच की मांग की

गुवाहाटी। गौहाटी उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (जीएचसीबीए) ने सोमवार को कहा कि वह मांग करता है कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ उत्तर गुवाहाटी के रंगमहल में स्थापित की जाए। सोमवार को बार एसोसिएशन के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि हम पूर्वोत्तर के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच चाहते हैं, यह कुछ ऐसा है जिसकी मांग हमने 10 साल पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से की थी। गौहाटी उच्च न्यायालय की बार एसोसिएशन ने सोमवार को तीन घंटे का धरना दिया और गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को रंगमहल में स्थानांतरित करने के सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ अपना विरोध जताया। एसोसिएशन के एक सदस्य ने कहा कि अगर सरकार गौहाटी उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ को स्थानांतरित करने के बजाय रंगमहल में पूर्वोत्तर के सर्वोच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करती है, तो हमारा मानना है कि इससे असम की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि यह कदम सरकार और आंदोलनकारी बार एसोसिएशन दोनों के लिए मध्य मार्ग का काम करेगा। बार एसोसिएशन ने पूर्ण न्यायालय प्रस्ताव का भी विरोध किया, जिसे प्रस्तावित स्थानांतरण के संबंध में बार को विश्वस में लिए बिना पारित -शेष पृष्ठ दो पर

हावड़ा में सुवेंदु अधिकारी और पुलिस के बीच हाथापाई

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी सोमवार को हावड़ा के बेलगछिया इलाके में भूस्खलन प्रभावित लोगों से मिलने गए थे। इस दौरान पुलिस ने सुवेंदु अधिकारी को रास्ते में रोकने की कोशिश की। जहां दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और झड़प में भाजपा नेता का बायां हाथ चोटिल हो गया। सुवेंदु अधिकारी ने अधिकारियों पर उनके साथ हाथापाई करने और उन्हें चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। दरअसल, हाल ही में हावड़ा जिले के बेलगछिया इलाके में सड़क धंसने से पानी की पाइपलाइन फट गई, जिससे कई घरों में दरारें आ गईं। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वह प्रभावित परिवारों से मिलने गए थे, लेकिन ममता पुलिस ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की और मेरे साथ झड़प भी की। उन्होंने अधिकारी गुलाम मुर्तजा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह आक्रामक हो गए थे, -शेष पृष्ठ दो पर

सुप्रभात

कोई भी अपने लिए आलसी होने की और मुर्ख होने की योजना नहीं बनाता। ये सारी चीजे तो तभी होती है जब आपके पास कोई योजना नहीं होती है।

-लेरी वीनगेट

लीलावती फाउंडेशन ने गुवाहाटी में सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए

गुवाहाटी/मुंबई। लीलावती फाउंडेशन ने सोमवार को कहा कि उसने 300-350 करोड़ रुपए के निवेश से गुवाहाटी में एक सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने के लिए असम सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और यह सुविधा पूर्वोत्तर क्षेत्र और बांग्लादेश और भूटान जैसे पड़ोसी देशों की जरूरतों को पूरा करेगी। मुंबई स्थित फाउंडेशन ने कहा कि वह पूरे भारत में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने के लिए कई राज्यों के साथ चर्चा के अंतिम चरण में है। इसने कहा कि गुवाहाटी में प्रस्तावित 250 से 300 बिस्तरों वाली सुविधा ऑन्कोलॉजी और कार्डियोलॉजी जैसी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा गंतव्य बनने के लिए तैयार है। फाउंडेशन के संस्थापक और -शेष पृष्ठ दो पर

पहली बार मुख्य न्यायाधीश ने सभी सामग्री सार्वजनिक की : उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली (हि.स.)। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने न्यायिक जवाबदेही और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के मुद्दे पर सोमवार को संसद भवन स्थित अपने कक्ष में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की। इस दौरान सभापति ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के उस निर्णय की सराहना की जिसमें उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश -शेष पृष्ठ दो पर

कांग्रेस ने राज्य सरकार पर *विफल* परीक्षा प्रणाली का आरोप लगाया

गुवाहाटी। गुवाहाटी शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को बामुनी मैदम में असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड (एएसएसईबी) के सामने हाल ही में हुए प्रश्नपत्र लीक की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रिपुन बोरा के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने मामले की गहन जांच की मांग की। कार्यालय के सामने भारी भीड़ जमा हो गई, प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां पकड़ रखी थीं और नारे लगा रहे थे, जिसके कारण किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। बोरा ने कहा कि आज हमें विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है -शेष पृष्ठ दो पर

न्यूज गैलरी

अब प्याज पर नहीं लगेगी एक्सपोर्ट ड्यूटी : शिवराज सिंह

नई दिल्ली (हि.स.)। प्याज के मूल्य पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को महत्वपूर्ण घोषणा की। सोमवार को कृषि मंत्रालय में मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह -शेष पृष्ठ दो पर

कनाडा में चुनाव की घोषणा, 28 अप्रैल को होगी वोटिंग

ओटावा (हि.स.)। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए संघीय चुनाव की घोषणा कर दी। उन्होंने रविवार को गवर्नर-जनरल मैरी साइमन से मुलाकात कर संसद को भंग करने का अनुरोध किया। साइमन ने कार्नी के अनुरोध स्वीकार कर लिया। कनाडा में चुनाव 28 अप्रैल को होंगे। कार्नी का मुकाबला उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलीवर से होगा। सीएनएन -शेष पृष्ठ दो पर

उत्तराखंड में 136 मदरसे सील, सीएम ने दिए जांच के आदेश

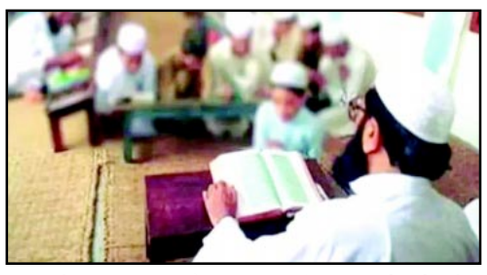

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए अब उनकी फंडिंग की गहन जांच करने का निर्णय लिया है। प्रदेशभर में अब तक 136 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इन मदरसों को मिलने वाले धन के स्रोतों की पूरी तरह से जांच की जाए। प्रदेश में पिछले एक महीने से अवैध मदरसों को लेकर प्रशासन ने सख्त अभियान चला रखा है। अब तक जिन मदरसों को सील किया गया है, उनके पास न तो पंजीकरण के वैध दस्तावेज थे और न ही -शेष पृष्ठ दो पर

जमीअत ने एससी का दरवाजा खटखटाया

नई दिल्ली (हि.स.)। उत्तराखंड सरकार ने पिछले दिनों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की सिफारिश को आधार बनाकर मदरसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इसके खिलाफ जमीअत उलमा-ए-हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इस संबंध में मंगलवार, 25 मार्च को -शेष पृष्ठ दो पर

सांसदों की सैलरी में 24 हजार का इजाफा, पेंशन-भत्ता भी बढ़ा

नई दिल्ली। केंद्र ने सोमवार को संसद सदस्यों (एमपी) और पूर्व संसद सदस्यों के वेतन, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में संशोधन की घोषणा की, जिसमें वर्तमान सांसदों के वेतन में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की गई। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में वर्तमान सदस्यों के दैनिक भत्ते तथा पेंशन में भी वृद्धि की गई है तथा पूर्व सदस्यों के लिए पांच वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन की भी घोषणा की गई है। वेतन में वृद्धि को आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया गया है। संशोधित भुगतान इस प्रकार हैं :

वेतन : संसद सदस्यों का -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

MURTI AVAILABLE

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shivling, Nandi etc. **ARTCLE WORLD,** S-29, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, **Ph. : 94350-48866, 94018-06952**

पीएम से मिले पीयूष-जयशंकर यूएस ट्रेड टैरिफ को लेकर हुई चर्चा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी व्यापार शुल्कों पर चर्चा करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। बैठक में अगले महीने से शुरू होने वाले अमेरिका से संभावित पारयूएसपरिक शुल्कों को संबोधित करने की भारत की रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों और भारत पर उनके प्रभाव पर चिंताएं प्रमुख विषय थे। सरकार चीनी एफडीआई में ढील देने और गैर-व्यापार बाधाओं की खोज करने पर भी विचार कर रही है। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि भारतीय अधिकारियों के साथ व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल 25 से 29 मार्च तक भारत का दौरा करेगा। दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच इस समूह का नेतृत्व करेंगे। यह यात्रा भारत के साथ उत्पादक और संतुलित व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारतीय व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने इस महीने की शुरुआत में लगभग एक सप्ताह अमेरिका में बिताया, जहां उन्होंने व्यापार चर्चा की, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2 अप्रैल से पारयूएसपरिक टैरिफ लगाने की योजना के कारण भारतीय निर्यातकों में चिंता पैदा हो गई। पिछले महीने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने 2025 की शरद ऋतु तक व्यापार समझौते के पहले चरण पर काम करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पिछले सप्ताह कहा था कि भारत और अमेरिका टैरिफ संबंधी मुद्दों को सुलझाने तथा द्विपक्षीय व्यापार समझौते की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा कर रहे हैं। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि हम व्यापार और निवेश के मामलों पर भारत सरकार के साथ अपने चल रहे सहयोग को महत्व देते हैं और इन चर्चाओं को रचनात्मक, न्यायसंगत और दूरदर्शी तरीके से जारी रखने की आशा करते हैं।

बजाज फिन्सर्व लार्ज एंड मिड कैप फंड ने मनाई पहली सालगिरह

गुवाहाटी/पुणे। बजाज फिन्सर्व एएमसी ने अपने बजाज फिन्सर्व लार्ज एंड मिड कैप फंड की पहली वर्षगांठ मनाई। अपने पहले ही साल में इस फंड ने निफ्टी लार्ज मिडकैप 250 टीआरआई बेंचमार्क को पीछे छोड़ते हुए डायरेक्ट प्लान में 8.07 फीसदी और रेगुलर प्लान में 6.45 फीसदी का संचयी रिटर्न दिया। अपने शुरुआती वर्ष में, फंड ने लगातार बढ़ते संचयी अल्फा को बनाए रखते हुए बेहतर प्रदर्शन किया। 28 फरवरी, 2025 तक, फंड ने डायरेक्ट प्लान में अपने बेंचमार्क से 8.07 प्रतिशत और रेगुलर प्लान में 6.45 प्रतिशत बेहतर प्रदर्शन किया। पिछला प्रदर्शन भविष्य में जारी रह भी सकता है और नहीं भी। बजाज फिन्सर्व लार्ज एंड मिड कैप फंड एक ओपन-एंडेड इक्विटी फंड है, जो लार्ज और मिड कैप कंपनियों में निवेश करता है। यह फंड अपनी खास *मोट* (एमओएटी) निवेश रणनीति के लिए जाना जाता है, जिसमें ऐसे शेयरों का चयन किया जाता है जो लंबी अवधि तक टिकाऊ प्रतिस्पर्धी बढ़त रखते हैं। कंपनी का मानना है कि मजबूत प्रबंधन, ब्रांड वैल्यू, लागत लाभ, पेटेंट और बिक्री की अर्थव्यवस्था जैसे तत्व, किसी भी कंपनी को प्रतिस्पर्धियों से आगे ले जाते हैं। वर्तमान में यह फंड 69 उच्च गुणवत्ता वाले शेयरों में निवेश कर रहा है, और बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच भी स्थिर प्रदर्शन के साथ निवेशकों के लिए दीर्घकालिक धन सृजन का मजबूत जरिया बन रहा है। इस अवसर पर बजाज फिन्सर्व एएमसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गणेश मोहन ने कहा कि हमने यह फंड निवेशकों को स्थिरता और विकास दोनों का लाभ दिलाने के उद्देश्य से शुरू किया था। बाजार की अनिश्चितता के बावजूद हमने गुणवत्ता वाली कंपनियों में निवेश की अपनी रणनीति पर डटे रहते हुए अच्छा रिटर्न दिया है। बजाज फिन्सर्व एएमसी के मुख्य निवेश अधिकारी, श्री निमेश चंदन ने कहा कि बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड-कैप फंड गुणवत्ता पर ध्यान देने और लंबे समय तक निवेश में बने रहने वाले निवेशकों के लिए है।

विहिप गुवाहाटी की बैठक राम महोत्सव की तैयारी

गुवाहाटी (हिंस)। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) गुवाहाटी की ओर से आज बताया गया है कि विहिप की गुवाहाटी महानगर जिले की एक महत्वपूर्ण पूर्ण बैठक पिछले दिनों पानबाजार मुख्य कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में 12 प्रखंडों के अध्यक्ष और सचिवों सहित महानगर जिले के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष सबिन राजखोवा ने की, जबकि सचिव रतुल डेका ने बैठक का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए संगठन को और मजबूत करने की योजनाओं को सामने रखा। गुवाहाटी विभाग के सचिव चंदन राभा ने आगामी छह महीनों की कार्ययोजना प्रस्तुत की। गुवाहाटी महानगर जिला प्रचार सचिव मुकुटेश्वर गोस्वामी ने सोमवार को बताया कि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में राम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

असम-मिजोरम सीमा के पास नौ बर्मीज मवेशी बरामद

कछार (हिंस)। गुप्त सूचना के आधार पर कछार पुलिस की एक टीम ने सोमवार तड़के असम-मिजोरम सीमा के पास धोलाई थाना क्षेत्र के रामपू पुंजी जंगल इलाके में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान नौ बर्मीज (म्यांमार) मूल के मवेशी बरामद किए गए, जिन्हें तस्करी कर लाए गए होने की आशंका है। इसके अलावा, एक मारुति ऑल्टो कार भी जब्त की गई। हालांकि, मवेशियों को लाने वाले संदिग्ध अंधेरे और दुर्गम इलाके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे।

निश्चिंतपुर टर्मिनल पर मालगाड़ी का पहला रेक सफलतापूर्वक पहुंचा

गुवाहाटी (हिंस)। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पूसी रेलवे) ने त्रिपुरा में अगरतला के निकट निश्चिंतपुर टर्मिनल पर पहला मालगाड़ी सफलतापूर्वक पहुंचाकर एक उल्लेखनीय माइलस्टोन हासिल किया है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह 10-20 बजे गुवाहाटी के निकट तेतेलिया में स्टार साइडिंग से सीमेंट लदे 11 बीसीएन वैगनों की एक खेप निश्चिंतपुर टर्मिनल पहुंचा। यह उपलब्धि अगरतला-अखौरा नई रेल लिंक परियोजना के तहत माल परिवहन संचालन में एक ऐतिहासिक क्षण था। वरिष्ठ रेल अधिकारियों द्वारा सफलतापूर्वक संयुक्त निरीक्षण के बाद पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव ने अगरतला-निश्चिंतपुर सेक्शन को माल परिवहन के लिए मंजूरी प्रदान की। माल परिवहन के लिए इस टर्मिनल के खुलने से अधिक बोझ वाले गुड्स शेडों जैसे जिरनीया और लामडिंग मंडल के अन्य प्रमुख स्थानों पर भीड़भाड़ काफी कम हो जाएगी। वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर, यह पहल लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाती है और क्षेत्र में माल परिवहन को सुव्यवस्थित करती है।

जोराबाट में दो चोर गिरफ्तार

गुवाहाटी (हिंस)। गुवाहाटी के बाहरी इलाके में स्थित जोराबाट पुलिस चौकी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चला कर भारी मात्रा में चोरी के सामान समेत दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि पुलिस चौकी क्षेत्र में चलाए गए अभियान के दौरान एक टाटा मैजिक वाहन (एएस-01एचसी-7340) से भारी मात्रा में चोरी की सामग्री बरामद की गई। चोरों के पास से रेलवे ट्रैक में इस्तेमाल होने वाली 12 भारी लोहे के एंगल, 2 खाली बड़े प्लास्टिक के ड्रम जो चोरों द्वारा सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से डीजल तेल चुराने के लिए नियमित रूप से इस्तेमाल किए जाते थे और एक छोटा कटर चाकू बरामद किया गया है। इस मामले में दो चोरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान बाबू बोड़ो (19) और बाबुल साहा (23) के रूप में की गई है। गिरफ्तार दोनों आरोपी गुवाहाटी के नारंगी के पाथरक्वारी के रहने वाले बताए गए हैं। बरामद वाहन को नूनमाटी क्षेत्र से चुराया गया था और लोहे की सामग्री सेक्टर-1 से चुराई गई थी।

पृष्ठ एक का शेष

असम विस में हंगामा...

कि कांग्रेस विधायक नूरुल हुदा ने उनके साथ मारपीट की। मुख्यमंत्री शर्मा ने मामले को गंभीरता से लिया और विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी से सच्चाई उजागर करने के लिए जांच का आदेश देने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा कि अगर यह साबित हो जाता है कि कांग्रेस विधायक नूरुत हुदा ने नुमाल मोमिन के साथ मारपीट की है, तो बिना देरी किए पुलिस मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री शर्मा ने स्पीकर दैमारी से अनुरोध किया कि वे सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दें ताकि वे मोमिन से बात कर सकें और आगे की कार्रवाई करने से पहले घटना के विवरण की पुष्टि कर सकें। सीएम शर्मा ने कहा कि मुझे मोमिन से एक व्हाट्सएप संदेश मिला है कि नूरुल हुदा ने उसके साथ मारपीट की है। मैं स्पीकर से अनुरोध करता हूं कि अगर हुदा ने वास्तव में उसके साथ मारपीट की है तो पुलिस केस दर्ज करें। मैं स्पीकर विश्वजीत दैमारी से अनुरोध करता हूं कि वे एक बार डिप्टी स्पीकर से बात करके विवरण की पुष्टि करें और फिर कार्रवाई करें। विवाद के बीच, कथित हमले की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिससे राजनीतिक बहस तेज हो गई। वहीं एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम ने कहा कि एक भाजपा विधायक विपक्षी विधायक पर हमला करने के लिए अपनी सीट से भागा। अध्यक्ष हमें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आत्मरक्षा के लिए बांस की ढाल लेकर आए हैं। हम इस ढाल को संसद के अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया ने कहा कि आज का विरोध असम विधानसभा में शुक्रवार को हुई घटना के खिलाफ है। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक विपक्षी विधायकों पर हमला करने के लिए दौड़े। हमने उस अनियंत्रित विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि अगली बार जब कोई उनके भाषण में बाधा डालेगा तो वह दस गुना अधिक आक्रामक हो जाएंगे।

गौ हमारी मां ...

कि मैं असम के विकास के लिए व्यवस्थागत परिवर्तन की सिफारिश करता हूं। हम असम से बाहर सुपारी के निर्यात को रोकने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए असम में सुपारी संसाधन केंद्र स्थापित करने हेतु समझौता किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले किसी ने हमें ऐसे सुझाव क्यों नहीं दिया? समस्या को खत्म करने की इच्छा सभी में होनी चाहिए। उन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम को लेकर कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के साथ काम कर रही है। 2021 से अब तक इस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार में लिप्त 24 राजपत्रित अधिकारियों, 80 द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों और 30 से अधिक अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि *ड्रग्स के खिलाफ असम* सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि असम को नशा मुक्त बनाने की ईमानदार कोशिश है। हम असम को नशे और आतंकवाद की भूमि बनने नहीं देंगे और इसलिए यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 2021 से अब तक असम में 2600 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

राज्य में सुपारी उद्योग ...

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे विधानसभा में यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एडवांटेज असम 2.0 सम्मेलन के दौरान दो औद्योगिक घरानों ने असम में सुपारी इकाइयां स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे असम की सुपारी राज्य से बाहर जाने से रुकेगी और किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि असम सीधी भर्ती परीक्षा (एडीआरई) का पारदर्शी संचालन, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल का व्यापक उपयोग, भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी और ड्रग्स और अवैध शराब जैसे कुछ रैकेटों पर कार्रवाई वर्तमान सरकार की पारदर्शिता की पहचान है। राज्य में गैंडों के अवैध शिकार के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में गैंडों के अवैध शिकार के मामलों में भारी कमी आई है। इस मामले पर पिछली सरकार से सवाल करते हुए मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या गैंडे के सींगों का इस्तेमाल चुनाव के वित्तपोषण के साधन के रूप में किया गया था। शर्मा ने पूछा कि पिछली सरकार के दौरान गैंडों के शिकार के मामले 20 या उससे भी ज़्यादा हो गए थे। अब यह घटकर साल में एक या दो रह गए हैं। राज्य में इतने सारे गैंडे क्यों मारे गए? क्या उनके पास शिकार की समस्या को रोकने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं थी? क्या इसका उद्देश्य चुनावों के लिए पैसे जुटाना था? उन्होंने आगे कहा कि उमरंगसो रैट होल खनन त्रासदी के बाद सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया है कि न्याय और पारदर्शिता बरकरार रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने डेटा प्राप्त करने के लिए उपग्रहों के रूप में नई तकनीक का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा, हमने मामले की जांच के लिए न्यायमूर्ति अनिमा हजारिका आयोग का गठन भी किया है। विपक्ष के नेता ने भी अदालत में मामला दायर किया है। मामले का न्यायोचित तरीके से फैसला किया जाएगा। यह सरकार किसी को भी कोई संरक्षण नहीं देगी।

असम विस ने वित्त ...

के साथ, उन्होंने आम जनता के लिए कोई नया कर प्रस्तावित नहीं किया, लेकिन लगभग 1.5 लाख वेतनभोगी लोगों को अतिरिक्त राहत दी। असम में विधानसभा चुनाव अगले साल मार्च-अप्रैल के दौरान होने की संभावना है, जिससे यह हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली दूसरी भाजपा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। वित्त मंत्री ने उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए हरी चाय की पत्तियों के लिए कर अवकाश को दो और वर्षों के लिए बढ़ाने की घोषणा की थी, जबकि 6.8 लाख बागान श्रमिकों को 5,000 रुपए का एकमुश्त नकद लाभ देने की पेशकश की थी। नेउग ने एक प्रमुख योजना - *मुख्यमंत्री की जीवन प्रेरणा* का भी उल्लेख किया था कि जो नौकरी की तलाश की अवधि के दौरान स्नातकों को एक वर्ष के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उन्होंने कहा था कि यह पहल एक बेरोजगारी भत्ता नहीं है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों और उद्यमशीलता की गतिविधियों की तैयारी में उनकी मदद करने के लिए एक प्रेरक समर्थन (प्रेरणा) है। मुझे असम के सरकारी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों से वर्ष 2025 में उत्तीर्ण होने वाले स्नातकों को 2,500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इसके अलावा, नेउग ने जीवन धारा और एक महीने में 120 यूनिट तक की खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में 1 रुपए प्रति यूनिट की कटौती करने का प्रस्ताव दिया था, जिससे 48 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिली।

बार एसोसिएशन ने राज्य...

किया गया था। बार एसोसिएशन के एक सदस्य ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या हाईकोर्ट सरकार के आदेश के अनुसार स्थानांतरित होगा। उन्होंने पूछा कि हम क्यों जाएंगे? आज, एक सरकार सत्ता में आकर उच्च न्यायालय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की बात करती है। बाद में, दूसरी सरकार आएगी और कहेगी कि हमें दूसरे क्षेत्र में जाना चाहिए। यह कैसे काम करेगा? इससे पहले, 19 मार्च को बार एसोसिएशन ने गौहाटी उच्च न्यायालय को रंगमहल में प्रस्तावित स्थानांतरण से संबंधित घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए एक असाधारण आम सभा की बैठक (ईओजीएम) बुलाई थी। गहन विचार-विमर्श के बाद, आम सभा ने प्रस्तावित समिति में भाग नहीं लेने का संकल्प लिया, जैसा कि 13 मार्च, 2025 को मुख्य न्यायाधीश, गौहाटी उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और जीएचसीबीए, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम बार काउंसिल और ऑल असम लॉयर्स एसोसिएशन (एएएलए) के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में सुझाव दिया गया था। एसोसिएशन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि वह उच्च न्यायालय के प्रस्तावित स्थानांतरण के प्रति अपना विरोध दोहराती है तथा रंगमहल में न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थापना की देखरेख के लिए गठित किसी भी समिति का हिस्सा न बनने का निर्णय लेती है। आम सभा ने प्रस्तावित स्थानांतरण के संबंध में पूर्ण न्यायालय के संकल्प की एक प्रति मांगने तथा उन परिस्थितियों पर स्पष्टीकरण मांगने का भी संकल्प लिया, जिनके तहत बार से परामर्श किए बिना ऐसा निर्णय लिया गया, जो न्यायिक प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण हितधारकों में से एक है।

लीलावती फाउंडेशन ने गुवाहाटी ...

अध्यक्ष प्रशांत मेहता ने पीटीआई को बताया कि असम सरकार ने इस परियोजना के लिए लंबी अवधि के पट्टे पर 3 एकड़ जमीन आवंटित की है, और इस परियोजना के लिए धन ऋण, इक्विटी और दान के मिश्रण से जुटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना के दो से तीन साल में पूरा होने की उम्मीद है। यह ऐसे क्षेत्र को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा, जो विशेष स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने में लंबे समय से चुनौतियों का सामना कर रहा है। मेहता ने कहा कि यह परियोजना गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने के हमारे समर्पण का प्रमाण है। असम का रणनीतिक स्थान और राज्य सरकार का मजबूत समर्थन इसे चिकित्सा पर्यटन और विशेष चिकित्सा सेवाओं के लिए एक आदर्श केंद्र बनाता है। मुंबई के बांद्रा में लीलावती अस्पताल चलाने वाली संस्था ने कहा कि वह गोवा, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद और बेंगलुरु सहित पूरे भारत में मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज स्थापित करने पर भी सक्रिय रूप से विचार कर रही है। मेहता ने कहा कि हम गोवा, दिल्ली, राजस्थान (जयपुर), तेलंगाना (हैदराबाद) और कर्नाटक (बेंगलुरु) के साथ बातचीत के उन्नत चरण में हैं। हम इन राज्यों में इसी तरह की सुविधाएं स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश कर रहे हैं। पांच वर्षों में, हम अधिकांश महानगरों में 3,000 बिस्तरों वाले अस्पताल स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।

पहली बार मुख्य...

यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर नकदी मिलने से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सार्वजनिक करने तथा मामले की आगे की जांच के लिए एक आंतरिक समिति गठित करने का निर्णय लिया। सभापति ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्य न्यायाधीश ने पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपने पास उपलब्ध सभी सामग्री को सार्वजनिक डोमेन में रखा है और न्यायालय के पास कुछ भी रखे बिना इसे साझा किया है। उन्होंने न्यायपालिका की आंतरिक प्रतिक्रिया को सही दिशा में उठाया गया कदम बताया और कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा समिति का गठन और उनकी सतर्कता भी एक ऐसा कारक है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। धनखड़ ने कहा कि न्यायपालिका और विधायिका जैसी संस्थाएं अपने उद्देश्य को सबसे अच्छे तरीके से पूरा करती हैं जब उनका आंतरिक तंत्र प्रभावी, तेज और जनता के विश्वास को बनाए रखने वाला होता है। सभापति ने कहा कि यह पहली बार है कि न्यायपालिका के प्रमुख, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने बहुत ही प्रभावशाली, पारदर्शी तरीके से कार्रवाई शुरू की है, इसलिए समिति के परिणाम की प्रतीक्षा करना सार्थक होगा क्योंकि इससे हमें अपने विचार के लिए संपूर्ण सामग्री प्राप्त करने में मदद मिलेगी। धनखड़ ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुझाव दिया कि संसदीय प्रथा के अनुरूप, इस मुद्दे पर सदन के नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सुझाव उचित है और जल्द एक बैठक निर्धारित की जाएगी।

कांग्रेस ने राज्य सरकार ...

क्योंकि हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। वे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार एक सामान्य परीक्षा भी आयोजित नहीं कर सकी। परीक्षा आयोजित करने में सरकार की खामियों को उजागर करते हुए बोरा ने आरोप लगाया कि अनियमितताएं लंबे समय से चल रही हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसी घटना हुई है। हम इस सरकार के तहत लंबे समय से ऐसी अनियमितताएं देख रहे हैं। उल्लेखनीय है कि गणित के पेपर लीक होने के दो दिन बाद, एचएस प्रथम वर्ष की परीक्षा का अर्थशास्त्र का प्रश्नपत्र शनिवार को परीक्षा से एक घंटे पहले कथित रूप से लीक हो गया, जिसके कारण एएसएसईबी को शेष विषयों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। एएसएसईबी डिवीजन टू (पूर्व नाम असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (एएचएसईसी)) ने परीक्षा शुरू होने से महज एक घंटे पहले शनिवार सुबह करीब 8 बजे कथित लीक की रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की। एएसएसईबी ने एक आदेश में स्कूल निरीक्षकों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कुछ संस्थानों ने परीक्षा से एक दिन पहले गणित के प्रश्नपत्रों के सीलबंद पैकेट खोले थे। बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, 10 जिलों - बरपेटा, बोजाली, कछार, धेमाजी, हैलाकांदी, कामरूप मेट्रो, लखीमपुर, माजुली, नगांव और नलबाड़ी - के पंद्रह निजी संस्थानों ने कथित तौर पर परीक्षा की निर्धारित तिथि और समय से पहले पैकेटों की सील तोड़ दी थी, जो मानक प्रक्रिया का उल्लंघन है।

हावड़ा में सुवेंदु ...

जिसकी वजह से मैं घायल हो गया। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। बेलगछिया इलाके में लैंडफिल के पास रहने वाले 70 से ज्यादा परिवार इससे प्रभावित हैं। जब मैं पीड़ित परिवारों से मिलने गया तो पुलिस ने मुझे पीड़ितों से मिलने से रोकने के लिए मौके पर ही हाथापाई की। अधिकारी गुलाम मुर्तजा मुख्य अपराधी थे, जो आक्रामक हो गए। इस कारण मेरे हाथ में चोट लग गई। एक भाजपा कार्यकर्ता पानी में गिर गया। उन्होंने कहा कि ममता पुलिस को यह समझना चाहिए कि मैंने कम्युनिस्ट शासन से लड़ाई लड़ी है। उनके बुरे साम्राज्य को उखाड़ फेंका है। एक समय ऐसा भी था जब मैं जिस रास्ते से यात्रा करने वाला था, वहां बम पाए गए थे। आप मुझे धमका नहीं सकते या मुझे रोक नहीं सकते। मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूं और फिर से और भी जोश के साथ ऐसा करूंगा। बेलगछिया इलाके में हाल ही में आई आपदा के बाद कई दिनों तक लोगों को पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। लोग अब भी सदमे में हैं।

उत्तराखंड में 136 मदरसे ...

संचालन से संबंधित कोई अधिकृत प्रमाण था। सरकार को संदेह है कि इन मदरसों को हवाला या विदेशी फंडिंग के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसी कारण, अब इनकी वित्तीय गतिविधियों की पूरी जांच की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तराखंड में करीब 500 अवैध मदरसे चल रहे हैं, जिनके संचालन की कोई अधिकृत जानकारी प्रशासन के पास नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन मदरसों का खर्च कैसे चलता है और शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन कहां से आता है? सरकार को आशंका है कि ये मदरसे धर्म की आड़ में अवैध फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि जांच के बाद ही यह पता चलेगा कि क्या इन मदरसों को दूसरे देशों से फंडिंग मिल रही है या नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि जिला स्तर पर एक विशेष कमेटी बनाई जाए, जो अवैध मदरसों की फंडिंग की जांच करेगी। इस कमेटी को प्रत्येक मदरसे के दस्तावेज, बैंक खाते और आय-व्यय का पूरा ब्योरा खंगालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यदि किसी मदरसे की फंडिंग में गड़बड़ी या संदिग्ध लेन-देन पाया जाता है, तो संबंधित मदरसे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों जैसे जसपुर, बाजपुर, किच्छा, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, पछवादून और हरिद्वार में अवैध मदरसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकार को सूचना मिली है कि इनमें से कई मदरसे बिना अनुमति के चल रहे हैं और यह सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। प्रशासन अब इन मदरसों के स्रोतों और उद्देश्यों की गहन जांच कर रहा है। सोमवार को देहरादून जिला प्रशासन ने सहसपुर में स्थित एक बड़े मदरसे को सील कर दिया। इस मदरसे ने बिना किसी अधिकृत अनुमति के एक मंजिल का निर्माण कर लिया था। प्रशासन ने पहले ही इसे नोटिस जारी किया था, लेकिन मदरसा प्रबंधन ने नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा, जिसके बाद कार्रवाई की गई। अब तक उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में सील किए गए अवैध मदरसों का विवरण इस प्रकार है : ऊधम सिंह नगर : 64 मदरसे, देहरादून : 44 मदरसे, हरिद्वार : 26 मदरसे, पौड़ी गढ़वाल : 2 मदरसे प्रमुख है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में अवैध मदरसों, मजारों और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अवैध रूप से संचालित मदरसों की फंडिंग की जांच के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। कोई भी गैरकानूनी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जमीअत ने एससी ...

सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई हो सकती है। एनसीपीसीआर ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया था कि कथित रूप से शिक्षा का अधिकार एक्ट से संबंध न रखने वाले सभी मदरसों को बंद करा दिए जाए। राष्ट्रीय आयोग ने कहा था कि मदरसों में बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दी जा रही है और यह बच्चों के अधिकार के खिलाफ है। आगे यह भी कहा गया था कि मदरसों में बच्चों को न केवल उचित शिक्षा बल्कि स्वस्थ वातावरण और विकास के अच्छे अवसर से भी वंचित रखा जा रहा है। सरकारी अधिकारियों ने उत्तराखंड में बड़े स्तर पर मदरसों के खिलाफ फिर कार्रवाई शुरू कर दी है। जमीअत उलमा-ए-हिंद का कहना है कि अब तक इस कार्रवाई में बिना पूर्व सूचना के बहुत से मदरसों को जबरदस्ती बंद करवा दिया गया, हालांकि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि जब उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की पहले कार्रवाई की गई थी तो जमीअत उलमा-ए-हिंद ने इस साजिश को विफल बनाने के लिए मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम याचिका दाखिल की थी। इसमें उन सभी दावों को चुनौती दी गई थी जिसके बाद अदालत ने उन सभी नोटिसों पर रोक लगा दी जो विभिन्न राज्यों विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों को जारी किए गए थे। उत्तराखंड में मदरसों के खिलाफ इस कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए आज जमीअत ने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। जमीअत का कहना है कि उतराखंड में मकतबों और मदरसों, जो केवल मुस्लिम समुदाय के बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के माध्यम हैं, के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप और उन्हें लगातार भयभीत किया जा रहा है।याचिका में कहा गया है कि हमारे मदरसे और मकतब जो शुद्ध रूप से गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक धार्मिक शिक्षा संस्थाएं हैं, यह बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के चल रहे हैं। लेकिन अचानक पहली मार्च 2025 से अब तक सरकारी अधिकारी हमारे मदरसों में आ रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि हमें यह मकतब और मदरसे बंद करने होंगे।

सांसदों की सैलरी ...

मासिक वेतन 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर 1,24,000 रुपए कर दिया गया है।

दैनिक भत्ता : दैनिक भत्ता 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है।

पेंशन : संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के लिए मासिक पेंशन 25,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दी गई है।

अतिरिक्त पेंशन : पूर्व सांसदों को सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन में भी 2,000 रुपए से 2,500 रुपए की वृद्धि मिलेगी।

यह कदम कर्नाटक सरकार द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दिए जाने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है, जिससे विधानसभा में तीखी बहस शुरू हो गई है। विपक्षी नेता आर अशोक के नेतृत्व में भाजपा ने सार्वजनिक अनुबंधों में मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सरकार के खिलाफ नारे लगाए। वेतन वृद्धि के बारे में निर्णय दो संशोधन विधेयकों के माध्यम से दिया गया था - कर्नाटक मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक 2025 और कर्नाटक विधानमंडल सदस्यों के वेतन, पेंशन और भत्ते (संशोधन) विधेयक 2025।

अब प्याज पर नहीं ...

चौहान ने कहा कि अब प्याज के निर्यात पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि हमारे किसानों द्वारा मेहनत से उगाया गया प्याज बिना किसी शुल्क के वैश्विक बाजारों तक पहुंचे और उन्हें बेहतर कीमत और लाभकारी मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों को लाभकारी मूल्य देना, उचित दाम सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता और प्रतिबद्धता है। पहले प्याज पर 40 प्रतिशत एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी लेकिन जब प्याज के दाम गिरने लगे और किसानों को कम कीमत मिलने लगी, तब सरकार ने फैसला किया कि प्याज के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दी जाए। अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 20 प्रतिशत एक्सपोर्ट ड्यूटी भी पूरी तरह हटा दी जाए।

कनाडा में चुनाव की ...

की खबर के अनुसार, कार्नी ने चुनाव की घोषणा करते हुए देश के लोगों से कहा कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से निपटने और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जनादेश मांग रहे हैं। जनवरी में अपने पूर्ववर्ती जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की घोषणा के बाद लिबरल नेता कार्नी प्रधानमंत्री बने हैं। सर्वेक्षणों से संकेत मिला है कि अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध और कनाडा की संप्रभुता के लिए ट्रंप की धमकी के बाद लिबरल पार्टी की लोकप्रियता में उछाल आया है। कार्नी ने कहा कि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका कनाडा पर कब्जा कर ले। हम ऐसा नहीं होने देंगे।

उद्योग मंत्री बिमल बोरा ने इन्वेस्ट इंडिया के उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया

गुवाहाटी। उद्योग, वाणिज्य और सार्वजनिक उद्यम मंत्री बिमल बोरा ने आज गुवाहाटी में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत इन्वेस्ट इंडिया के उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। असम औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम के अंतर्गत बामुनी मैदाम इंडस्ट्री पाम स्थित जिला उद्योग केंद्र भवन में कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मंत्री ने कहा कि एडवांटेज असम द्वारा लाए गए निवेश प्रस्तावों को यदि उचित ढंग से क्रियान्वित किया जाए तो इससे असम के औद्योगिक क्षेत्र में नए क्षितिज खुलेंगे। उन्होंने कहा कि अनेक युवाओं ने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर स्टार्टअप के माध्यम से उद्यमी के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया है। मंत्री ने कहा कि इन्वेस्ट इंडिया का पूर्वोत्तर कार्यालय निवेश के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है और यह पूर्वोत्तर राज्यों के औद्योगिक विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। मंत्री ने कहा कि एडवांटेज असम 2.0, जिसे असम के संसाधनों को क्षमता में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है, आर्थिक विकास को गति देगा और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का उल्लेख किया कि देश पूर्वोत्तर के विकास के बिना विकसित नहीं हो सकता है। उद्घाटन समारोह में इन्वेस्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी निभ्रुति रॉय ने कहा कि असम में देश की 40 प्रतिशत जलविद्युत पैदा करने की क्षमता है और इस संबंध में राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण है। असम औद्योगिक विकास निगम के निदेशक मनबेन्द्र प्रताप सिंह ने अपने भाषण में कार्यालय के उद्घाटन को असम के औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक पहलू बताया। यह कार्यालय औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न नीतियों एवं सुविधाओं के संबंध में निवेशकों एवं सरकार के बीच उत्प्रेरक का कार्य करेगा। इस अवसर पर इन्वेस्ट इंडिया के राज्य एवं विशेष कार्यक्रम विभाग के उपाध्यक्ष कुलतुमोनी कार्तिकेयन, एनईडीएफआई की उत्तर पूर्व टीम प्रमुख डॉ. गीतिमा कृष्णा, असम औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक और फिनार के अध्यक्ष पी उदय प्रवीण, एनजी लोहिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कांग्रेस, एआईयूडीएफ ने विस में भाजपा विधायक के विरुद्ध किया विरोध-प्रदर्शन

गुवाहाटी (हिंस)। असम विधानसभा में सोमवार को कांग्रेस और एआईयूडीएफ विधायकों ने जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया। वे भाजपा विधायक रूपज्योति कुर्मी पर 21 मार्च को विपक्षी सदस्यों पर हमले की कोशिश और अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे थे। नेता प्रतिपक्ष देबब्रत सैकिया के नेतृत्व में विपक्षी विधायकों ने कुर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और स्पीकर विश्वजीत दैमारी पर उचित हस्तक्षेप न करने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायकों ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया, जबकि एआईयूडीएफ विधायकों ने खुद की रक्षा के प्रतीक के रूप में बांस की संरचनाएं लाने का प्रयास किया। हालांकि, सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें विधानसभा के अंदर ले जाने से रोक दिया। एआईयूडीएफ विधायक रफीकुल इस्लाम ने कहा कि भाजपा विधायक विपक्षी सदस्यों पर हमला करने के लिए अपनी सीट छोड़कर आते हैं, लेकिन स्पीकर हमें सुरक्षा नहीं देते। इसलिए, हमने आत्मरक्षा के लिए ये बांस की बाधाएं बनाई हैं। इस हंगामे के बीच, स्पीकर दैमारी ने सदन की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया।

असम विधानसभा पर धब्बा

कांग्रेस-एआईयूडीएफ विधायकों के विरुद्ध हो कड़ी कार्रवाई : दिलीप सैकिया

गुवाहाटी (हिंस)। असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने कहा है कि असम विधानसभा में आज का दिन इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। विधानसभा के पवित्र परिसर में एक अभूतपूर्व और शर्मनाक घटना घटी। उन्होंने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कांग्रेस और एआईयूडीएफ विधायकों के उग्र व्यवहार को अत्यंत चिंताजनक करार दिया। सैकिया ने कहा कि सबसे चौंकाने वाली घटना में बंगाली मूल के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस विधायक नुरुल हुदा ने एक स्वदेशी जनजातीय समुदाय के नेता उपाध्यक्ष डॉ. नुमल मोमिन पर शारीरिक हमला कर दिया। इसी दौरान, एआईयूडीएफ के विधायकों ने भी हाथों में बांस की लाठियां लेकर विधानसभा में जबरन घुसने की कोशिश की, जिससे पूरे सदन में अफरा-तफरी मच गई। भाजपा अध्यक्ष सैकिया ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस प्रकार की आक्रामक मानसिकता असम के भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ के बंगाली मूल के विधायकों का यह उग्र व्यवहार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सैकिया ने कहा कि असम की जनता कांग्रेस और एआईयूडीएफ विधायकों की इस हरकत से आहत और चिंतित है। उन्होंने इस घटना को असम विधानसभा के इतिहास का काला अध्याय करार देते हुए कहा कि यह पहली बार है जब विधानसभा के उपाध्यक्ष पर हमला हुआ और एआईयूडीएफ के विधायकों ने बांस की लाठियों के साथ विधानसभा परिसर में घुसने की कोशिश की। भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक द्वारा एक स्वदेशी जनजातीय प्रतिनिधि पर हमले को असम के भविष्य के लिए एक खतरनाक संकेत बताया। उन्होंने घटना की तत्काल जांच की मांग की और कांग्रेस विधायक नुरुल हुदा की अविलंब गिरफ्तारी की अपील की। इसके साथ ही, सैकिया ने असम विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे एआईयूडीएफ विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, जिन्होंने सदन में अशांति फैलाने का प्रयास किया।

असम विस : रूपज्योति कुर्मी को संयम बरतने की मुख्यमंत्री की सलाह

विधानसभा में मनोरंजन तालुकदार के वायरल ऑडियो टेप पर चर्चा

गुवाहाटी (हिंस)। असम विधानसभा में आज विधायक मानव डेका ने विधायक मनोरंजन तालुकदार के वायरल ऑडियो टेप का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने विधायक रूपज्योति कुर्मी को संयम बरतने की नसीहत दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर मैं सदन में होता तो ऐसा नहीं होता। यह मामला सदन से बाहर नहीं जाना चाहिए था। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। उन्होंने विपक्ष के नेता से इस मामले को यहीं समाप्त करने की अपील की। इसी दौरान विधायक मानव डेका ने आरोप लगाया कि विधानसभा के बाहर चंदा मांगने के बहाने ब्लैकमेलिंग की जा रही है। उन्होंने स्पीकर से इस मामले पर *शो कॉज* नोटिस जारी करने की मांग की। दूसरी ओर, मनोरंजन तालुकदार ने कहा कि वह इस मामले को अदालत में ले जाएंगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगर यह सच है तो यह अनुचित है। मैं इस पर गहरा अफसोस व्यक्त करता हूं। ऐसी हरकतें निंदनीय हैं। इसके बाद मनोरंजन तालुकदार ने कहा कि मुझे बिना जांच के निंदा क्यों झेलनी पड़ी? जब तक जांच नहीं होती, कोई मुझे दोषी नहीं ठहरा सकता। इस पर अध्यक्ष ने घोषणा की कि मनोरंजन तालुकदार का मुद्दा आगामी विधानसभा सत्र में चर्चा के लिए रखा जाएगा।

राज्यपाल ने महिला अचीवर्स पुरस्कार 2025 समारोह में भाग लिया

गुवाहाटी। असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने आज यहां वार्षिक फिक्की महिला संगठन महिला अचीवर्स पुरस्कार 2025 समारोह में भाग लिया। समारोह के दौरान राज्यपाल श्री आचार्य ने फिक्की से जुड़ी सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दीं और समाज में उनके उल्लेखनीय योगदान की सराहना की। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डाला, भारत की समृद्ध विरासत और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति को रेखांकित किया। राज्यपाल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की महिलाओं की असाधारण प्रतिभा की प्रशंसा की तथा मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन और मैरी कॉम, एथलीट हिमा दास, तथा *हरगिला बाइडू* पूर्णिमा देवी बर्मन और अन्य प्रेरणादायक हस्तियों का हवाला दिया। उन्होंने प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण तथा समावेशी आर्थिक एवं सामाजिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के महत्व पर बल दिया। राज्यपाल श्री आचार्य ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की पहल की भी सराहना की। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में महिला उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया तथा कहा कि भारत में 80 लाख से अधिक महिला उद्यमी हैं। राज्यपाल ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी तथा उन्हें राष्ट्र की प्रगति और विकास में योगदान देते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित महिलाओं को एफएलओ महिला अचीवर्स अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। मिजोरम की सबसे युवा विधायक बैरिल वन्नेइहसांगी को उनकी उल्लेखनीय राजनीतिक उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। मणिपुर की प्रसिद्ध लोक गायिका मंगका मयंगलम्बम को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मणिपुर की मोइरांगथेम मुक्तामणि देवी को एक कुशल उद्यमी के रूप में मान्यता दी गई। असम की मीनाक्षी चेतिया को आशा कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनके प्रभावशाली कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, तथा असम की मीनाक्षी दास को बाइक सवार के रूप में उनकी प्रेरक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। एफएलओ ट्रेलब्लेजर अवार्ड्स 2025 में सामग्री निर्माण में उत्कृष्टता के लिए नीलाक्षी आर शर्मा, दूरदर्शी उद्यमिता के लिए पायल अग्रवाल जैन, सांस्कृतिक प्रतीक के लिए अभिश्रुति बेजबरुवा, खेल में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए वर्षा रानी की उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) की महिला शाखा फिक्की एफएलओ की स्थापना महिलाओं को उद्यमी, व्यापारिक नेता और पेशेवर के रूप में अपनी क्षमता तलाशने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी।

एसएसबी ने डिजल सहित पिकअप गाड़ी किया जब्त

कोकराझाड़ (विभास)। सीमा चौकी नहारानी के द्वारा बीआईटी पोस्ट के पास एसएसबी टीम के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक महिन्द्रा पिक-अप (न. एएस-15 ए-सी 0509) जो भूटान से भारत आ रहे, को संदेहात्मक तौर पर रोक कर वाहन चालक से पूछताछ के दौरान स्पष्ट जानकारी व कागजात प्राप्त नहीं होने के उपरांत वाहन की तलाशी ली गई। जिसमें भूटान से अवैध तरीके से वाहन के नीचले भाग में एक अतिरिक्त टैंक बनवाकर उसमें लगभग 100 लीटर से ऊपर डीजल लाते हुए चालक पकड़ा गया। जिसे जब्त कर अवैध डीजल, वाहन सहित संदिग्ध व्यक्ति को लैंड कस्टम ऑफिस हातीसार, दादगिरी को अग्रिम कार्रवाई हेतु सुपूर्द किया गया।

आगामी योग दिवस को लेकर देशभर में कार्यक्रम शुरू, मेघालय के लिविंग ब्रिज पर किया योग

मेघालय/नई दिल्ली (हिंस)। आगामी योग दिवस के लिए देशभर में आयोजित हो रहे योग कार्यक्रमों के तहत पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान ने सोमवार को मेघालय के नोंग्रियाट में डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया। यह प्रतिभागियों के लिए अपने आप में अनूठा अनुभव रहा। आयुष मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि योग धैर्य, शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। यह कार्यक्रम इस बात का प्रतीक है कि कैसे प्राचीन ज्ञान आधुनिक स्वास्थ्य के साथ सहजता से मिलकर जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसके साथ इस प्राचीन पुल पर किए गए प्रत्येक आसन से संदेश स्पष्ट है कि योग केवल स्टूडियो तक सीमित नहीं है। उल्लेखनीय है कि लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने की प्रक्रिया में है। यह ब्रिज रबर और अंजीर के पेड़ों की जड़ों से पूरी तरह प्रकृति रूप से बुना गया है, जो एक जीवंत मार्ग बनाता है और समय के साथ मजबूत होता जाता है। मंत्रालय ने बताया कि इस पुल पर योग कार्यक्रम का आयोजन इस बात का प्रतीक है कि कैसे योग सिर्फ एक अभ्यास से कहीं ज़्यादा प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने वाली ज़िंदगी जीने का तरीका है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र की ओर से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किए जाने के बाद से भारत ने अपने कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्थलों पर योग सत्र आयोजित करके दुनिया के योग अनुभव को फिर से परिभाषित किया है। ताजमहल से लेकर कोणार्क सूर्य मंदिर तक, गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर लाल किले तक, हर जगह इतिहास, संस्कृति और खुशहाली की कहानी बयां करती है। अब लिविंग रूट ब्रिज भी इस सूची में शामिल हो गया है।

नेत्र, आवर मिशन, देयर विजन के तहत 21 रोगियों की नि:शुल्क कैटरैक्ट सर्जरी

गुवाहाटी। *नेत्र, आवर मिशन, देयर विजन के तहत* पहले चरण में 21 रोगियों के लिए नि:शुल्क कैटरैक सर्जरी का आयोजन किया। यह सर्जरी डॉ. अनिल अग्रवाल द्वारा कुशलता से की गई थी। लाभार्थी असम के विभिन्न हिस्सों से थे। जेसीआई गुवाहाटी पाथफाइंडर्स और बिमलारूप ने लाभार्थियों की वित्तीय सीमाओं को समझा और उन्हें आवश्यक सर्जरी प्राप्त करने में मदद की। जेसीआई जोन 25, रीजन डीके जेडवीपी, जेसी सुमित पोद्दार और जेडडी, कम्युनिटी डेवलपमेंट, जेसी परास ने इस अवसर को संबोधित किया और जेसीआई गुवाहाटी पाथफाइंडर्स और बिमलारूप के प्रयासों की प्रशंसा की। जेसीआई गुवाहाटी पाथफाइंडर्स की अध्यक्ष, जेसी मिनाक्षी दामानी ने समाज के लिए अधिक करने पर जोर दिया और कहा कि उनका संगठन कम से कम 50 ऐसी नि:शुल्क सर्जरी का आयोजन करने की योजना बना रहा है। उन्होंने इस नोबल पहल के लिए योगदान देने वाले दानदाताओं का भी धन्यवाद किया। परियोजना के अध्यक्ष जेसी रितु बैद और जेसी राघव बहेती थे। निकिता बैद, जेसी कमल रोहिल्ला, जेसी प्रिया तिवारी और जेसी पूनम दामानी ने भी एबल समर्थन प्रदान किया।

फेदरलाइट ने किया एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ

गुवाहाटी। ऑफिस फर्नीचर समाधानों में अग्रणी नाम फेदरलाइट ने कार्यस्थल डिजाइन में नवीनतम डिजाइनों और रुझानों को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित अपने विशेष अनुभव केंद्र के उद्घाटन किया। महानगर के भांगागढ़ स्थित रुद्राक्ष मॉल के सामने सेठी ट्रस्ट बिल्डिंग स्थित 8,000 वर्ग फीट में फैली हुई है। इस एक्सपीरियंस सेंटर में आधुनिक व्यवसायों, शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं की विकसित होती फर्नीचर जरूरतों को पूरा करने वाले उत्पादों की एक व्यापक श्रृंखला मौजूद है। इस शोरूम का उद्घाटन एसोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट्स, असम के अध्यक्ष आर्किटेक्ट रंजीव बरुवा, फेदरलाइट ग्रुप के एसोसिएट डायरेक्टर किरण चेलाराम और खेतान कार्पेट कॉर्पोरेशन के पार्टनर अभिषेक खेतान द्वारा किया गया। उद्घाटन के अवसर पर किरण चेलाराम ने कहा कि हमारे नए शोरूम के साथ, हम असम और गुवाहाटी शहर के गतिशील राज्य की अधिक प्रभावी ढंग से सेवा करने की उम्मीद करते हैं। हम कॉरपोरेट्स, छोटे व्यवसाय के मालिकों, उद्यमियों और सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्रों को गुवाहाटी में हमारे नए एक्सपीरियंस सेंटर पर आने और फेदरलाइट के लिए जाने जाने वाले अत्याधुनिक डिजाइनों और अभिनव समाधानों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये कारक सरकारी कार्यालयों, आतिथ्य व्यवसायों और क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों को एर्गोनोमिक, स्टाइलिश फर्नीचर की आपूर्ति करने के पूरी तरह से सक्षम हैं। इस मौके पर अभिषेक खेतान ने कहा कि फेदरलाइट का यह अनुभव केंद्र सिर्फ एक शोरूम से कहीं अधिक है-यह डिजाइन प्रेरणा और विचारों का केंद्र है। फर्नीचर रेंज में एर्गोनोमिक क्लासरूम सीटिंग, आधुनिक और चुस्त बेंच, लाइब्रेरी रैक, हॉस्टल फर्नीचर, सॉफ्ट-सीटिंग और प्रेजेंटेशन स्टेशन शामिल हैं जो किसी भी शैक्षणिक संस्थान को बहस, चर्चा और विचार-विमर्श के केंद्र में बदल सकते हैं जहां छात्र कामयाब हो सकते हैं।

कोकराझाड़ में ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार

कोकराझाड़ (हिंस)। कोकराझाड़ में आज एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया गया। कोकराझाड़ विज्ञान महाविद्यालय के समीप से पकड़े गए ड्रग्स तस्कर की पहचान बहारुल परमानिक (39), भोटगांव, भदैयागुरी गांव के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों की सूचना के आधार पर पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। कोकराझाड़ पुलिस ने बहारुल परमानिक को पकड़ने के साथ ही उसके पास से 34 ड्रग्स से भरे कंटेनर और 27, 910 रुपये बरामद किए। साथ ही एक टीवीएस मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

नगांव में सुर साधना संगीत महाविद्यालय का वार्षिक समारोह समापन

नगांव। सुर साधना संगीत महाविद्यालय का वार्षिक समारोह 21 मार्च से 23 मार्च तक आयोजित किया गया, जिसमें सौ से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह की शुरुआत प्रख्यात कवि, लेखक और आलोचक चिदानंद देव गोस्वामी ने दीप प्रज्ज्वलित कर की। प्रद्युत मिश्रा, प्राचार्य प्रताप सिंह, वरिष्ठ लेखक व पत्रकार अजय महतो अतिथि के रुप में उपस्थित थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात उस्ताद प्रद्युत मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुर साधना संगीत महाविद्यालय के अध्यक्ष नव कुमार महंत ने की। चिदानंद देव गोस्वामी ने अपने भाषण में संगीत की तुलना सूर्य की किरणों से करते हुए कहा कि जिस तरह सूर्य की किरणें मानव मन को जागृत कर सकती हैं, उसी तरह संगीत भी मानव हृदय को मोहित कर सकता है। अपने भाषण में मुख्य अतिथि प्रदुत मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि संगीत साधना का एक रूप है जो व्यक्ति को दुनिया पर विजय पाने में मदद कर सकता है। कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा कई शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियां दी गईं, जिनमें स्नेहा मीर का ख्याल, कुमार दत्ता का भजन और कस्तूरी देवी की गजल शामिल था। दर्शकों ने इन प्रस्तुतियों की खूब सराहना की। कार्यक्रम में कुशल दास और अतुल महंत का तबला वादन भी लोगों का मन मोह लिया। समारोह में जून राजखोवा, मुनींद्र गोस्वामी, देबला शर्मा, जोनमणि बोरा चिदानंद देव गोस्वामी, रंजन बेजबरुवा और दो सौ से अधिक अभिभावक तथा गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन सुर साधना संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य शुवागमोनी महंत के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से संस्थान के छात्रों और शिक्षकों की प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ, जिसे दर्शकों ने सराहा।

संपादकीय

न्यायपालिका की साख दांव पर

देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने तीन न्यायाधीशों की जांच समिति गठित की है, तो दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने आवास पर 15 करोड़ रुपए मिलने के आरोपों को नकार दिया है, बल्कि सख्ती से खारिज भी किया है। यह कोई सामान्य आरोप नहीं है। जस्टिस आम आदमी भी नहीं हैं। उनके जरिए देश की न्यायपालिका की साख दांव पर है। आम नागरिक का न्यायपालिका में विश्वास संदेहास्पद हो गया है। न्याय ही सवालिया हो गया है। सर्वोच्च अदालत के प्रख्यात वकील हैरान हैं, लेकिन साफ कह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा की छवि अच्छी और पारदर्शी है। यदि नकदी बरामद किया गया है, तो वह न्यायाधीश के मूल आवास से नहीं किया गया है। ऐसे सरकारी आवास में कई कमरे होते हैं। उनमें से 'आउटहाउस' वाले कमरे में, जो जेनरेटर के पास है, 14 मार्च की रात्रि आग लगी थी। जज का परिवार उस समय दिल्ली से बाहर था। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की सूचना के बाद जस्टिस वर्मा और परिजन अगले ही दिन लौट आए। दरअसल यह खबर और घटनाक्रम तब से राजनीतिक गलियारों, अदालतों और मीडिया में सुर्खियां बना है, जब एक प्रख्यात अंग्रेजी अखबार ने खबर छाप दी कि न्यायाधीश के आवास से 15 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। तभी देश में सनसनी फैल गई। यह एक सेवारत न्यायाधीश पर बेहद गंभीर और भ्रष्टाचार का आरोप है। कुछ सवाल मौजू हैं। आखिर नकदी नोट किसने देखे और बरामद किए? यदि नोट मिले हैं, तो 'रिकवरी मेमो' कहां है? नकदी कहां जमा है और दिल्ली पुलिस सार्वजनिक तौर पर खामोश क्यों रही? आखिर इतना धन कहां से आया और 15 करोड़ रुपए की गिनती किसने की? क्या यह 'काली कमाई' का मामला है? ऐसा नहीं है कि अदालतें भ्रष्टाचार से अछूती रही हैं। बीते 5 साल के दौरान अदालतों में भ्रष्टाचार की 1631 शिकायतें दर्ज की गई हैं। उनके निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं हैं। शायद इस प्रकरण के निष्कर्ष भी बहुत जल्दी सार्वजनिक न किए जाएं, क्योंकि एक न्यायाधीश के खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी, आपराधिक प्रक्रिया बेहद जटिल और लंबी है। बेशक संविधान के अनुच्छेद 124 (4 और 5) में प्रावधान हैं, जिनके तहत न्यायाधीशों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन यह भी इतना सपाट और आसान नहीं है। महाभियोग के जरिए सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन संसद में आज तक महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका है। अब तीन न्यायाधीशों की जांच में आरोप साबित भी हो जाते हैं, तो वह रपट केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजी जाती है। मंत्रालय उस रपट को राष्ट्रपति को प्रेषित करता है। सिफारिश स्वीकार होने पर राष्ट्रपति महाभियोग के लिए संसद को भेजते हैं। संसद में महाभियोग प्रस्ताव दो-तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है, तभी जज को हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति आज तक नहीं आई। सच यह भी है कि निष्कर्ष सामने न आए और प्रधान न्यायाधीश और आरोपित जस्टिस सेवामुक्त ही हो जाएं, तो नकद राशि का क्या होगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने आवास पर 15 करोड़ रुपए मिलने के आरोपों को नकार दिया है, बल्कि सख्ती से खारिज भी किया है। यह कोई सामान्य आरोप नहीं है। जस्टिस आम आदमी भी नहीं हैं। उनके जरिए देश की न्यायपालिका की साख दांव पर है। आम नागरिक का न्यायपालिका में विश्वास संदेहास्पद हो गया है। न्याय ही सवालिया हो गया है। सर्वोच्च अदालत के प्रख्यात वकील हैरान हैं, लेकिन साफ कह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा की छवि अच्छी और पारदर्शी है। यदि नकदी बरामद किया गया है, तो वह न्यायाधीश के मूल आवास से नहीं किया गया है। ऐसे सरकारी आवास में कई कमरे होते हैं। उनमें से 'आउटहाउस' वाले कमरे में, जो जेनरेटर के पास है, 14 मार्च की रात्रि आग लगी थी। जज का परिवार उस समय दिल्ली से बाहर था। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की सूचना के बाद जस्टिस वर्मा और परिजन अगले ही दिन लौट आए। दरअसल यह खबर और घटनाक्रम तब से राजनीतिक गलियारों, अदालतों और मीडिया में सुर्खियां बना है, जब एक प्रख्यात अंग्रेजी अखबार ने खबर छाप दी कि न्यायाधीश के आवास से 15 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। तभी देश में सनसनी फैल गई। यह एक सेवारत न्यायाधीश पर बेहद गंभीर और भ्रष्टाचार का आरोप है।

सरकार इस कानून के जरिए मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण करना चाहती है

कर्नाटक में कांग्रेस का फैसला संविधान के खिलाफ

प्रभुनाथ शुक्ल

मुख्य विपक्षी भाजपा के कड़े विरोध के बाद भी सरकार अपने फैसले और हौसले पर अडिग दिखी।सरकार निर्माण क्षेत्र में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए चार फीसदी आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट यानी केटीपीपी अधिनियम में संशोधन की गई है। यह प्रस्ताव सबसे पहले 2024 में चर्चा में आया जब सिद्धारमैया सरकार ने मुस्लिम समुदाय को ठेकेदारी में आरक्षण देने की संभावना पर विचार शुरू किया। मार्च 2025 में बजट पेश करते समय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसकी आधिकारिक घोषणा किया था। सरकार का दावा है कि इस तरह के आरक्षण से सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को सशक्त करने और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ठेकेदारी में मुस्लिम आरक्षण का बिल आखिरकार शुक्रवार को शोर शराबे और हंगामे के बाद में राज्य विधानसभा में पारित कर दिया। मुख्य विपक्षी भाजपा के कड़े विरोध के बाद भी सरकार अपने फैसले और हौसले पर अडिग दिखी।सरकार निर्माण क्षेत्र में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए चार फीसदी आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट यानी केटीपीपी अधिनियम में संशोधन की गई है। यह प्रस्ताव सबसे पहले 2024 में चर्चा में आया जब सिद्धारमैया सरकार ने मुस्लिम समुदाय को ठेकेदारी में आरक्षण देने की संभावना पर विचार शुरू किया। मार्च 2025 में बजट पेश करते समय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसकी आधिकारिक घोषणा किया था। सरकार का दावा है कि इस तरह के आरक्षण से सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को सशक्त करने और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। जबकि सरकार की असली मंशा मुस्लिम वोटरों पर है। फिलहाल भजपा बिल के खिलाफ अदालत का रुख करेगी या आंदोलन के जरिए हिन्दुओं का ध्रुवीकरण करेगी यह वक्त बताएगा। सरकार इस कानून के जरिए मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। फिलहाल आम गरीब मुस्लमानों को इस कानून से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि किसी भी सरकारी टेंडर लेने के लिए अच्छी ख़ासी पूँजी होनी चाहिए। सरकार इस तरह का कानून लाकर एक तीर से कई निशाना साधना चाहती है। कांग्रेस को लेकर वह मुसलमानों में एक सहानुभूति पैदा करना चाहती है। दूसरी तरफ सरकार के बेहद करीबी संबंध रखने वाले दौलतमंद मुस्लिमों को बेहतर मौका देना चाहती है। मुस्लिम मतों को हमेशा अपने पाले में रखने के लिए यह तुष्टिकरण की सबसे उम्दा नीति है। जबकि यह संविधान विरोधी है। राज्य में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए अदालत में जाने का फैसला किया है। भजपा का आरोप है कि संविधान में धर्म आधारित आरक्षण का विकल्प नहीं है। धार्मिक आधार पर आरक्षण दिए जाने का खुद बाबा साहब भीम राव आम्बेडकर ने विरोध किया था। आगरा में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उन्होंने खुद कहा था कि धर्म परिवर्तन के बाद हमें अब आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने इसे कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया है और दावा किया है कि

यह संविधान के खिलाफ है, क्योंकि भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद और तेजस्वी सूर्या ने इसे असंवैधानिक और वोट-बैंक की रणनीति बताते हुए इसे दलित और पिछड़े वर्ग के हितों के खिलाफ बताया है। जबकि राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने साफ किया है कि यह आरक्षण केवल मुस्लिमों के लिए नहीं, बल्कि सभी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदायों के लिए है, हालांकि विवाद मुख्य रूप से मुस्लिम कोटा पर केंद्रित है। क्योंकि हमारे संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण का कोई प्राविधान नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इसे राज्य के सभी अल्पसंख्यक समुदाय ईसाई, जैन, सिख के लिए बेहतर बताया है, लेकिन मूल विवाद धार्मिक आधार को लेकर है। क्योंकि सरकार सभी अल्पसंख्यकों की बात भले करती हो, लेकिन उसकी सोच में सिर्फ मुस्लिम हैं। क्योंकि राज्य में तक़रीबन 13 फीसदी मुस्लिमों की आबादी है। सामाजिक संगठनों ने इस आरक्षण पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। जबकि राज्य के मुसलमानों को ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ 1970 के दशक से मिल रहा है। कर्नाटक की राजनीति में अब यह बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसमें सामाजिक न्याय, संवैधानिकता, और वोट-बैंक की लड़ाई आमाने -सामने हो गईं है। कांग्रेस के लिए अहम सवाल यह है कि राहुल गाँधी देश भर में संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने संविधान बचाओ का नारा दिया था। फिर कर्नाटक में उन्हें संविधान की लुटिया डूबती क्यों नहीं दिखती। वहां भी तो कांग्रेस सरकार है। फिर मुसलमानों के वोट के लिए दोहरे चरित्र की राजनीति कहाँ तक जायज है। हिन्दुओं की उपेक्षा और मुसलमनों को सिर आँखों पर बिठाने की राजनीति कांग्रेस को ले डूबी। वैसे राहुल गाँधी और कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। क्योंकि साल 2012 में उन्होंने खुद मुस्लिम आरक्षण की वकालत किया था। देश में मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रहीं है उससे फिरहाल उम्मीद भी नहीं दिखती कि वह दिल्ली की राजनीति में वापसी करेगी। तुष्टिकरण की राजनीति ने कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा। महागठबंधन बनाने के बाद भी कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं हुआ। यह दीगर बात है कि लोकसभा में उसकी सीटें अधिक आयीं, लेकिन यह गठबंधन की वजह से हुआ। कर्नाटक में संविधान के खिलाफ धर्म के आधार पर मुस्लिम ठीकेदारों को सरकारी कामकाज में चार फीसदी आरक्षण का बिल पास हो गया, लेकिन राहुल गाँधी एक शब्द नहीं बोला। इस तरह की राजनीति कांग्रेस के पतन का एक और इतिहास लिखेगी। अगर धर्म के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों को सरकारी कामकाज में आरक्षण दिया जा रहा है तो हिन्दुओं को क्यों नहीं। कल दूसरे समुदाय के लोग भी इस तरह के आरक्षण की मांग करेंगे। बेगम एजाज रसूल ने संविधान सभा में धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण पर तीखा विरोध किया था। वह अकेली महिला थीं जिन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा था इस तरह के आरक्षण से मुसलमान, बहुसंख्यक समाज का विश्वास खो देगा। इसलिए ऐसे आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। यह आत्मघाती होगा और बहुसंख्यकों से अलग कर देगा।लेकिन आज हिंदू समाज के कथित हिमायती मुस्लिम आरक्षण की माला जप रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बीते साल मार्च में शिक्षा और रोजगार में मुसलमानों के लिए चार फीसदी आरक्षण की वकालत किया था। साल 2014 में महाराष्ट्र की तत्कालीन कॉंग्रेस सरकार ने शिक्षा और नौकरी में पांच फीसदी आरक्षण का अध्यादेश पारित किया था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने अपने एक बयान में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इससे कांग्रेस की सोच साफ हो जाती है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार तो मुसलमानों पर मेहरबन है। राज्य के बजट में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए एक हजार करोड़ का विशेष प्राविधान किया है।

दृष्टि कोण

खुदकुशी को न्योता देते मानसिक विकार

'मन के जीते जीत है, मन के हारे हार', यह उक्ति न जाने कितने लोगों के जीवन में प्रेरणा की स्रोत रही होगी। न जाने कितने लोगों ने इन शब्दों को आत्मसात कर जीवन की कठिनाइयों का न केवल सामना किया है, अपितु उन पर विजय पताका लहराई होगी। आज के संदर्भ में न तो कोई शब्द न ही कोई उक्ति, न कोई मुहावरा अथवा लोकोक्ति प्रचलित है, या इनका उपयोग केवल परीक्षा पास करवाने के लिए पाठ्यक्रम का हिस्सा मान लिया गया है। जहां तक अध्ययन एवं अध्यापन का सवाल है, ये सदैव ही व्यावहारिक होने चाहिए। शिक्षा व्यक्ति के चरित्र व व्यक्तित्व में झलकनी चाहिए, तभी शिक्षा का मूल उद्देश्य सार्थक होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आए दिन प्रदेश में खुदकुशी एवं आत्महत्या के समाचार विभिन्न माध्यमों से देखने या सुनने को मिलते हैं। खुदकुशी व आत्महत्या जैसे शब्दों के सुनने मात्र से डर की भावना सभी मनुष्यों में दस्तक देती है, फिर भी न जाने क्यों और कैसे जान बूझकर मौत के आगोश में चले जाते हैं, यह हम सभी के समक्ष चिंता का विषय है। मृत्यु अटल है, जिसका जन्म हुआ, उसकी मृत्यु निश्चित है, यह परम सत्य है। लेकिन जानबूझ कर मौत को गले लगाना उचित है, यह एक यक्ष प्रश्न है। प्रदेश में प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों में खुदकुशी का भयानक सच देखने को मिलता है। आए दिन समाचार पत्रों में खुदकुशी की खबरें छपी नजर आती हैं। परीक्षा परिणाम में असफलता से खुदकुशी, पारिवारिक झगड़ों के कारण खुदकुशी, प्रेम प्रसंग विफलता से खुदकुशी, सामाजिक दबाव से खुदकुशी व उच्च अधिकारी के दबाव के कारण खुदकुशी सहित न जाने खुदकुशी के कितने प्रकार हैं। अगर इन प्रकारों को गिनते जाएं तो न जाने फेहरिस्त कितनी लंबी होगी। खुदकुशी शब्द वैसे सुनने में तो उतना भयावह नहीं क्योंकि जहां खुशी का जिक्र आए वहां कैसा डर, परन्तु वास्तविकता तथा इसके परिणाम विशेषतः पारिवारिक दृष्टिकोण से भयावह एवं पीड़ादायक होते हैं। एक ऐसी पीड़ा जिसका वर्णन अल्फाज में करना मुमकिन नहीं होता। खुदकुशी की यह पीड़ा व इसकी तस्वीर तब गंभीर होती है, जब समाज के प्रबुद्ध एवं हजारों के प्रेरणास्रोत व्यक्ति इस रास्ते को अपनाते हैं। कौन भूल पाया होगा स्वर्गीय श्री अश्वनी कुमार को जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर व नागालैंड राज्य के राज्यपाल रहे। इसके अलावा भी वह अपने जीवन में न जाने कितने बड़े-बड़े पदों पर आसीन रहे हैं। ऐसे पद जिनको पाने के लिए व्यक्ति अपना सर्वस्व तक न्योछावर करने को तत्पर रहते हैं। ऐसी शख्सियत की खुदकुशी की खबर ने तो न जाने कितने लोगों को सोचने पर विवश किया होगा, कि मानसिक विकार के आगे पदवी एवं भोग-विलासिता का कोई महत्व नहीं। वहीं प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे स्वर्गीय श्री रामस्वरूप शर्मा सहित प्रदेश के न जाने कितने प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व मानसिक विकारों के चलते खुदकुशी जैसी कायराना हरकत को अंजाम दे गए। आए दिन नशे की लत में संलिप्त युवा भी खुदकुशी रूपी काल का ग्रास बनते जा रहे हैं। जब हम ऐसी घटनाओं पर मंथन करते हैं तो इनके पीछे मानसिक विकार स्पष्ट रूप से सामने आता है। देश-विदेश के अनेक शोध अध्ययन भी खुदकुशी के कारणों में मनोवैज्ञानिक विकारों को मुख्य कारण मानते हैं। वर्तमान में जहां एक ओर मानव जीवन विलासितापूर्ण है, वहीं मनुष्य कई प्रकार के मानसिक विकारों का शिकार है अथवा ग्रसित है। मानसिक विकार विभिन्न प्रकार के होते हैं। यद्यपि ये विकार व्यक्ति की आयु, लिंग एवं जीवन शैली के अनुसार पृथक-पृथक हो सकते हैं। चिंता विकार मुख्य सामान्य मानसिक विकार है तथा इसे मानसिक विकारों की जननी कहना भी उपयुक्त होगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि 'चिंता, चिता का कारण है।' चिंता किसे नहीं होती, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होता होगा जिसको चिंता न होती हो, लेकिन चिंता को अपने ऊपर हावी होने देना मानसिक विकार को उत्पन्न करता है। फलतः खुदकुशी का कारण बनती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज विश्व की लगभग 35 करोड़ जनसंख्या चिंता विकार की शिकार है। वहीं अवसाद जिसे डिप्रेशन कहते हैं, भी मानसिक विकार व रोग है जिसमें व्यक्ति को उदासी, निराशा व जीवन के प्रति रुचि की कमी महसूस होती है। अतः व्यक्ति का अपने प्रति यह उदासीन रवैया कभी-कभार खुदकुशी का कारण बनता है। द्विध्रुवी विकार भी एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति को अवसाद और उत्तेजना के बीच में बदलाव का अनुभव होता है। वहीं स्किजोफ्रेनिया मानसिक विकार में व्यक्ति को वास्तविकता की धारणा में गड़बड़ी का अनुभव होता है तथा उसी उधेड़बुन में व्यक्ति डूबा रहता है।

कुछ अलग

साहब का नाच...

एसडीएम साहब खूब नाचे। समारोह सरकारी, मंच सरकारी और सामने गायक भी सरकारी था, इसलिए नाचना उनके अधिकार क्षेत्र में था। अधिकारी पर अधिकार और अधिकार पर अधिकारी के नियंत्रण का अक्सर उसके नाच से पता चलता है। वैसे आजकल अधिकारियों या प्रशासनिक अधिकारियों को खुद को वश में रखना कहां संभव है। वे जहां-तहां नाच सकते हैं, बशर्ते उन्हें बताया जाए कि कब नाचना, कहां नाचना और कितना नाचना है। अधिकारियों को यह श्रेय तो दिया जा सकता है कि कई बार ये नाच-नाच में कहीं से कहीं पहुंच गए। ये परवाह नहीं करते कि उनके नाचने की वजह क्या या अदा क्या थी। वैसे यह व्यक्ति जब तक एसडीएम नहीं बना था, नाच के सख्त खिलाफ था। सोचता था पद पर पहुंचते ही सारे फिजूल के नाच बंद कर देगा, लेकिन अब उसे खुद को साबित करने के लिए नाचना पड़ता है। होली समारोह के मुख्यातिथि मंत्री थे, इसलिए नाचा ताकि वह अपनी अंगुलियों का एहसास करते। वह अब विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री तक की अंगुलियों को ही सुशासन मानता है। नेताओं की अंगुली उसके दायित्व को कहीं भी नचा सकती है। इसलिए वह देखते ही देखते कुशल नर्तक बन चुका है। वहां यूं तो हर अधिकारी नाच रहा है या नाच सकता है, यह दिखा रहा है, लेकिन उसने हुनर को अपनी तकदीर बना लिया। उसे कई बार शक हुआ कि वह नाचता नहीं, लेकिन जब उसके आगे नाचती हुई जनता भरोसा दिलाती है, तो यकीन हो जाता है कि दरअसल नाच-नाच में ही देश आगे सरक रहा है। कोई मस्जिद के आगे नाचे तो कोई हिंदू निकल आता है, नेता के आगे अधिकारी नाचे तो अव्वल निकल आता है। नाचने में हर जगह प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि जहां नाचते वहीं मंच पैदा हो जाता है। विपक्ष ने सरकार को पूरी तरह घेर रखा था। आरोप था कि सत्ता पक्ष का आंगन पूरी तरह टेढ़ा है, इसलिए उनकी तरह इस सरकार में नाच मुकम्मल नहीं है। विपक्ष को आंगन की चिंता थी कि कहीं यह और टेढ़ा हो गया, तो सत्ता में लौट कर वे इन्हीं अधिकारियों को पहले की तरह नचाएंगे कैसे। वर्तमान मुख्यमंत्री ने विपक्षी आरोपों को खारिज करके अपने आंगन में सभी अधिकारियों को नचाया, लेकिन मन में विचार किया कि क्यों न इनके नाच में कुछ नया जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री को चलाने वाले वरिष्ठ अधिकारी को पास बुलाकर कहा कि नाच में कुछ नया जोड़ो। अधिकारी ने अपने घुंघरू बजाते हुए कहा, 'हुजूर! यूं तो खजाना पूरी तरह खाली है, लेकिन कुछ चांदी के सिक्के बचे हैं। इनसे काम लायक घुंघरू बना कर अधिकारियों को पहना देते हैं।' सरकार ने मोहर लगे घुंघरू अधिकारियों को पहना दिए। अब बिना नाचे भी घुंघरू बजने लगे। जनता मंत्रमुग्ध हो गई। लोग अपने काम के लिए प्रशासन के पास जाते, लेकिन बजते घुंघरू सुनकर ही प्रसन्नता के भाव लिए लौट जाते। उन्हें खुशी है कि लोकतंत्र अब घुंघरू की तरह बजने लगा है। मुख्यमंत्री अब खुशी के लिए किसी भी अधिकारी को जनता के बीच नचा देते और जनता भी इस नाच को परंपराओं से जोडक़र अभिनंदन करती रहती। एक दिन जनता ने सुना कोई रात को भी घुंघरू बजा रहा है। उसे लगा अब तो सरकार रात को भी काम कर रही है, लेकिन घुंघरू सतर्क कर रहा था। लोग नींद में घरों से बाहर आए तो पता चला कि कोई किसान अपने बैलों को जोतने के लिए बचता-बचाता जा रहा था कि उनके गले से बंधे घुंघरू बज गए। सरकार को यह मंजूर नहीं था कि जनता बैलों और अधिकारियों के घुंघरुओं को एक ही अर्थ से सुनने लगे, अतः किसान के बैलों से घुंघरू हटाने का ऐलान हो गया।

देश दुनीया से

गंभीर पहल से ही सुलझेगा मणिपुर संकट

ये सभी कदम एक साथ और जल्दी-जल्दी उठाए गए। लेकिन काफी वक्त से यह लंबित था। स्वयं भाजपा और राज्य में भाजपा सरकार उम्मीद के विपरीत आस लगाए हुए थी कि 3 मई, 2023 को राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद से सरकार ने जो कमज़ोर कदम उठाए हैं, उनसे मामले सुलझ जाएंगे। बीच-बीच में कुछ समय के लिए शांति काल के अलावा लंबे समय तक टकराव अनवरत जारी रहा। इसके चलते मैतेई और कुकी जातियों के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण हो गए। समस्या कई अन्य कारणों से भी बढ़ गई, जिसके विभिन्न पहलुओं पर गंभीर प्रभाव पड़े। दो कारण भाजपा को ठोस कदम उठाने से रोक रहे थे : एक तो यह कि हम एक लोकतंत्र हैं, दूसरा यह कि राज्य में भी सत्ता उसी दल के पास थी, जिसकी केंद्र में सरकार है। ऐसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पार्टी के लिए शर्मिंदगी की वजह बनता क्योंकि इसका मतलब होगा कि खुद अपनी ही पार्टी की सरकार के कामकाज पर सवाल उठना। इसके अलावा, पार्टी को ऐसा उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया जो सभी को स्वीकार्य हो। हालांकि, सत्तारूढ़ पार्टी ने अब कड़ुवा घूंट पीना तय कर लिया है। देर आयद... दुरुस्त आयद! भविष्य की ओर देखते हुए, बहुत काम किए जाने की जरूरत है। सबसे पहले, समस्या की उत्पत्ति को देखें ताकि इससे निपटने में मदद मिल सके। म्यांमार में सैन्य शासन यानी जुंटा का अपने देश के संपूर्ण भूभाग पर, खासकर मणिपुर सीमा से लगते इलाके पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं है। इन क्षेत्रों में कई समूह अपनी सरकार से युद्धरत हैं और यहां तक कि कुछ इलाका उनके अधीन भी है। इसके अलावा, हिंसा के कारण, गोल्डन ट्राइंगल नाम से कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय ड्रग व्यापार रूट पर, मुख्य रूप से मोरेह शहर और मणिपुर के क्षेत्र से होकर गुजरने वाला, असर हो रहा था क्योंकि म्यांमार में अफीम की खेती के अंतर्गत

आने वाले क्षेत्रों में कमी आई थी या विस्तार नहीं हो पाया था। कई कुकी और संबंधित जनजातियां अपने स्थानीय रिश्तेदारों की मदद से मणिपुर में, मुख्य रूप से कुकी बहुल चूड़ाचांदपुर क्षेत्र में आन बसे और उन्होंने मणिपुर में भी अफीम उगाना शुरू कर दिया। स्थानीय लोग भी इस मुनाफेदार खेती में उनके साथ लग गए। जब यह बात राज्य सरकार के संज्ञान में आई, तो अवैध अप्रवासियों की पहचान करने के लिए कार्रवाई की गई। स्थानीय लोग,जिसकी पीठ पर बहुत अमीर एवं ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया का हाथ था,इस कार्रवाई का विरोध करने लगे। वे सरकार को पीछे हटने को मजबूर करना चाहते थे। उनके सौभाग्य से -और राज्य के दुर्भाग्य से- मैतेइयों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने वाली याचिका पर, मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा आए आदेश की गलत व्याख्या ने परेशानी पैदा करने का एक कारण प्रदान किया। 27 मार्च, 2023 को जारी इस आदेश में कहा गया था :'राज्य में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर शीघ्रता से विचार किया जाना चाहिए...'। इसमें केवल याचिका पर विचार करने के लिए आदेश था, न कि मैतेइयों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए। लेकिन कुकियों ने जानबूझकर इसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया, यह कहते हुए कि मैतेइयों को एसटी का दर्जा दे दिया गया है। हालांकि बाद में उच्च न्यायालय ने इस पैराग्राफ को हटा दिया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। दोनों पक्षों ने रैलियां निकालनी शुरू कर दीं, कुछ हिंसा भी भड़की और दोनों समुदायों द्वारा नाकेबंदी और जवाबी नाकेबंदी होने लगी। मैतेई बहुल घाटी में और कुकी एवं अन्य संबंधित जनजाति बहुल पहाड़ी इलाके में। स्थिति बदतर होती चली गई। हालात इतने खराब हो गए कि घाटी के लोग चुड़ाचांदपुर नहीं जा सकते थे और इसके विपरीत चूड़ाचांदपुर वाले घाटी में नहीं आ सकते। कुकियों ने एक अलग प्रशासन की मांग की। वे नहीं चाहते थे कि मैतेई लोगों को एसटी का दर्जा मिले क्योंकि उन्हें लगा कि इससे न केवल उनकी नौकरी का कोटा प्रभावित होगा बल्कि मैतेई लोग वैध तरीके से पहाड़ियों में जमीन भी खरीद सकेंगे। इसलिए, दोनों समुदायों के बीच एक तरह से पूर्ण पैमाने पर जातीय संघर्ष छिड़ गया, जिसमें हिंसा के कारण जान-माल का नुकसान हुआ और दोनों पक्षों के लोगों को विस्थापित होना पड़ा। आरोप है कि ड्रग माफिया ने अपनी मोटी जेबों के दम पर इस स्थिति को और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाई है। जल्द ही, सरकार और उसकी मशीनरी तक भी हिंसा का असर हो गया। दुर्भाग्यवश, दोनों समुदायों के बीच इस तरह का दोफाड़ कुछ हद तक पुलिस सहित सरकारी अमले में भी फैल गया। इसने स्थिति को और खराब कर दिया। अपराधी और निष्क्रिय पड़े विद्रोही समूह भी इस लड़ाई में कूद पड़े और इसका नतीजा यह हुआ कि सरकारी मशीनरी पूरी तरह चरमरा गई। पुलिस स्टेशनों और शस्त्रागारों पर भी हमला किया गया और 5,000 से अधिक हथियार लूट लिए गए। यह भी आरोप है कि पुलिस ने डरकर या मिलीभगत के कारण कई हथियार सौंपे। अवांछनीय तत्वों और हिंसक समूहों के हाथों में इतनी बड़ी संख्या में हथियार राज्य के लिए एक बड़ा खतरा हैं। इनमें से बमुश्किल एक-चौथाई हथियार ही बरामद हो पाए हैं। हालात और बदतर बने जब कुकी समूह हिंसा फैलाने के लिए ड्रोन तक का इस्तेमाल करने लगे। जाहिर है, उन्हें बहुत मदद हासिल है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के इस क्षेत्र में अपने निहित स्वार्थ हैं और उन्होंने दूसरों की लड़ाई में अपने लिए मौका पाया है। म्यांमार की स्थिति भी एक बड़ा कारक है। सरकार ने प्रतिक्रिया में और अधिक सैन्य बल भेजे हैं, लेकिन स्थिति पूरी तरह से उसके नियंत्रण में नहीं है। इसलिए, अब राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद संबंधित अधिकारियों के लिए काम करना आसान हो जाएगा। उनकी प्राथमिकता हिंसा को रोकना और लुटे हथियारों को वापस लेना होना चाहिए। एक साथ बहुत सारे काम करने की जरूरत है। मुख्य कार्यों में मामलों की जांच करना, राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, समुदायों के बीच सद्भाव और शांति बहाली, विस्थापितों का पुनर्वास, अवैध अप्रवासियों से निबटना, निष्पक्ष पुलिस और नौकरशाही बनाना, अवैध प्रवास और ड्रग्स और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए म्यांमार के साथ लगती सीमा सील करना, दूसरे देशों के मंसूबों को विफल करना और राजनीतिक प्रक्रिया बहाल करना शामिल है।

आप का नजरीया

शर्तिया इलाज

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शर्तिया इलाज की तारीख तय कर दी है और इस तरह अगला पूरा साल हिमाचल की स्वास्थ्य सेवाओं को समर्पित रहेगा। यह परीक्षा कठिन नहीं है, लेकिन इसे अमलीजामा पहनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री तमाम मेडिकल कालेजों को विश्व स्तरीय खाके में मजबूत करने का वादा करते हैं और इन्हें एम्स के मानकों में ढालने की वचनबद्धता से मशहूर करना चाहते है। मरीज तो आज भी तेरे दर पे आते हैं, मुश्किल यह कि मर्ज यहां मर्ज बनकर रह जाती। मुश्किल यह जानना नहीं कि कितने मरीज हर दिन हिमाचल से निकल कर बाहरी राज्यों में अपनी सेहत का हवाला देते हैं। यहां चिकित्सा की पूरी पद्धति आगे से आगे धकेल रही है। डिस्पेंसरी से अपना सफर शुरू करके मरीज मेडिकल कालेजों की असमर्थता में कहीं बाहर निकल जाता है। किसी भी अस्पताल के लिए बड़ी मशीनें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन मशीन उपचार नहीं करती। उपचार तो नियमित रूप से चिकित्सा सेवाओं की प्रतिष्ठा में निहित है। हुआ यह कि जिस शहर में मेडिकल कालेज बन गए, वहां चिकित्सा की परिक्रमा में निजी अस्पताल बढ़ गए। ये निजी चिकित्सा संस्थान सहारा हैं या सरकारी चिकित्सा संस्थानों को बेसहारा कर रहे हैं। चिकित्सा अब सेवा नहीं एक व्यापक धंधा है, जहां हर मरीज पर शिकारी निगाह है। पूरी चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। हमारे पास सुविधाएं आज भी कम नहीं और न ही दक्ष एवं विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी है, लेकिन छोटे से छोटे इलाज में भी कसरतें मेडिकल कालेज को करनी पड़ रही हैं। सारे के सारे मेडिकल कालेज एक ही दिशा में भाग रहे हैं। जहां मेडिकल कालेज हैं, वही क्षेत्रीय व जोनल अस्पताल भी खड़े हैं। चिकित्सा विभाग के ढांचे, संस्थानों के वर्गीकरण और भौगोलिक आवश्यकताओं के सांचे को अलग-अलग पैमानों से तरजीह देते हुए इनकी प्रासंगिकता बढ़ानी होगी। इन तमाम मेडिकल कालेजों की स्थापना ने पहले से कार्यरत कई चिकित्सा संस्थानों को बुरी तरह घायल करके एक तरह से अप्रासंगिक बना दिया है। जहां कैडर बड़ा, लेकिन उसका दायरा छोटा हो गया। आधे से ज्यादा चिकित्सा विभाग मेडिकल कालेजों में तशरीफ रखने लगा है, नतीजतन जिला स्तरीय सेवाएं भी बिगड़ गईं। उदाहरण के लिए टांडा मेडिकल कालेज की कीमत धर्मशाला के जोनल अस्पताल को आज भी चुकानी पड़ती है। यहां पंद्रह साल पहले के स्वीकृत पद आज भी अगर मेडिकल कालेज की भेंट हो रहे हैं, तो यह तस्वीर व्यवस्थागत है। अगर टीएमसी की अनावश्यक ओपीडी विभक्त होकर इसके आसपास के सिविल व जोनल अस्पताल में बंट जाए, तो उन्नत उपचार के मायने बदल जाएंगे। आश्चर्य यह कि इमरजेंसी के मायने क्षेत्रीय एवं जोनल अस्पतालों से बिगड़ कर मेडिकल कालेजों का भी नमक हराम कर रहे हैं। सरकार चिकित्सा संस्थानों से यह हिसाब तो ले कि हर दिन हिमाचल से बाहर कितने केस रैफर होते हैं, तो मालूम हो जाएगा कि हमारे बीच संवेदना कितनी बची है। अगर चिकित्सा सेवाओं को बेहतर व सक्षम बनाना है, तो रोग निष्पादन की औसत में सुधार का दैनिक ऑडिट होना चाहिए। हिमाचल में मेडिकल जरूरतें निरंतर बदल रही हैं और इसी वजह से निजी अस्पतालों का नेटवर्क सशक्त हो रहा है।

किसान नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर फूंका पंजाब सरकार का पुतला

सिरसा (हिंस)। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पंजाब सरकार द्वारा गुप्त स्थान पर रखे जाने से नाराज कालांवाली क्षेत्र के किसानों ने सोमवार को उपमंडल कार्यालय के सामने रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान व कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुंडिया के खिलाफ नारेबाजी कर उनका पुतला फूंका। किसान नेता गुरनाम सिंह देसूमलकाना, गुरदास सिंह, जरनैल सिंह कालांवाली, इकबाल सिंह तिलोकेवाला आदि ने कहा कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है।

बॉर्डर से हटाई गई किसानों की ट्रॉलियां आम आदमी पार्टी के विधायकों के घर से मिल रही है, जिसका प्रमाण किसानों के पास हैं। उन्होंने कहा कि किसान हमेशा से शांति से अपनी बात करना चाहते थे। किसानों की मांगें जायज हैं। केंद्र सरकार से पूछा गया था कि मांगें नाजायज लगती है, तो बता दें। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि जिस तरह आंदोलनकारियों के साथ बर्ताव किया गया, उससे देशभर के किसानों में रोष है। जगजीत सिंह डल्लेवाल का कोई पता नहीं है, उन्हें कहां रखा गया है। कई किसान नेता पटियाला जेल में बंद है। उनकी मांग है कि गिरफ्तार किए गए किसानों की जल्द से जल्द रिहाई की जाए।

युवा पीढ़ी को संस्कार और मार्गदर्शन की जरूरत : देवेंद्र कादियान

सोनीपत (हिंस)। गन्नौर में सोमवार को शिक्षांजलि समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसके बाद छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक देवेंद्र कादियान ने शिरकत की। अपने संबोधन में विधायक देवेंद्र कादियान ने कहा कि यह शिक्षा एक छोटे पौधे से विशाल बरगद की तरह विकसित होता है। शैक्षिक गुणवत्ता के साथ आज के दौर में युवा पीढ़ी को संस्कार और सकारात्मक मार्गदर्शन की जरूरत है, क्योंकि परिवारों का विस्तार हो रहा है। उन्होंने ऐसे आयोजनों को छात्रों की प्रतिभा निखारने का बेहतरीन मंच बताया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि नपाध्यक्ष अरुण त्यागी, शिक्षा विभाग से कप्तान दहिया सहित सुशील त्यागी, अजय यादव, मोती बत्रा, भावना जाग्या, शालू वाधवा, हरीश वाधवा मौजूद रहे। नन्हें कलाकारों को उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहित किया। आयोजक संजीव राय, निर्देशक शिल्पा राय, आरती त्यागी ने आभार व्यक्त किया। समापन में अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। यह आयोजन शिक्षा और संस्कृति के सामंजस्य का शानदार उदाहरण बना।

राणा सांगा पर अमर्यादित टिप्पणी से राजपूत सभा नाराज

जोधपुर (हिंस)। योद्धा महाराणा सांगा पर अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में सोमवार को मारवाड़ राजपूत सभा की ओर से पावटा बी रोड स्थित सभा भवन से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला गया। इसके साथ ही उप राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आपत्तिजनक टिप्पणी को राज्यसभा की कार्रवाई से हटाने और सांसद रामजीलाल की सदस्यता समाप्त करने की मांग की। मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमानसिंह खांगटा ने बताया कि गत 22 मार्च को सपा सांसद रामजीलाल ने राज्यसभा में न केवल आपत्तिजनक बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत टिप्पणी की थी। इन्होंने महाराणा सांगा, जो भारतीय इतिहास के महान योद्धा और स्वतंत्रता के प्रतीक है, को गद्दार कहकर न केवल उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है. बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को भी आहत किया है। अध्यक्ष खांगटा ने कहा कि इतिहास के अनुसार बाबर को भारत में बुलाने का कार्य दौलत खान ने किया था। महाराणा सांगा ने अपने पूरे जीवनकाल में भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ वीरता का प्रदर्शन किया। ऐसे में रामजीलाल सुमन द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पूरी तरह से अस्वीकार्य है और यह उनके पद की गरिमा के विपरीत है। ऐसी स्थिति में मारवाड़ राजपूत सभा व सर्व समाज की ओर से उप राष्ट्रप्रति के नाम ज्ञापन प्रेषित कर रामजीलाल की राज्यसभा सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द करने और राज्यसभा की कार्रवाई से उस आपत्तिजनक टिप्पणी को पूर्णत: हटाए जाने की मांग की गई है। बता दें कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने शनिवार को राज्यसभा में राणा सांगा के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

हाईटेंशन लाइन के टूटे तार से बाइक समेत 3 युवक जिंदा जलने के मामले में डिस्कॉम के जेईएन-लाइनमेन सस्पेंड

अजमेर (हिंस)। नागौर में हाईटेंशन लाइन के टूटे तार की चपेट में आने से बाइक समेत तीन युवक जिंदा जलने के मामले में डिस्कॉम प्रशासन ने जेईएन पवन कुमार व लाइनमैन रामदेव इनाणिया को सस्पेंड कर दिया है। दोनों का मुख्यालय नागौर कर दिया गया है। डिस्कॉम के चीफ इंजीनियर व डायरेक्टर टेक्नीकल मुकेश चंद बाल्दी ने बताया कि मृतकों को नियमानुसार पांच-पांच लाख का मुआवजा दिया जाएगा। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही जेईएन व लाइनमैन को निलंबित कर दिया है। हादसा खींवसर के भावंडा इलाके के मुंदियाड़ गांव में रविवार दोपहर 12 बजे हुआ था। इसमें मुंदियाड़ निवासी पीथाराम देवासी, कालूराम देवासी और जेठाराम देवासी बाइक से नजदीकी गांव कड़लू जा रहे थे। मुंदियाड़ से निकलने के बाद कुछ दूरी पर रास्ते में 11 केवी बिजली का तार टूटा पड़ा था। जैसे ही बाइक टूटे तार के ऊपर से गुजरी, करंट दौड़ गया। बाइक में आग लग गई और तीनों युवक उसकी चपेट में आ गए। मौके पर लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने बिजली विभाग को सूचना देकर सप्लाई बंद कराई।

राज्यपाल ने ली जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक

जयपुर/टोंक (हिंस)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने जिला परिषद सभागार टोंक में सोमवार को जिला स्तरीय अधिकारियों से संवाद कर विकास योजनाओं और जनहित के कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। बागडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करें और उनके जीवन में सुधार लाने के लिए जनहित की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें। राज्यपाल ने जल संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में संचित रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सुदूर गांवों और ढाणियों में सड़कों की बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, इस कार्य को प्राथमिकता से समयबद्ध सीमा में पूरा किया जाएं। जल जीवन मिशन में प्रत्येक परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं। पीएम सूर्य घर योजना और पीएम कुसुम योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को प्रेरित करें। राज्यपाल ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि राजीविका योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की उचित मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएं। उन्होंने किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओ की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, पीएम फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सॉयल हेल्थ कार्ड योजना को लेकर संबधित विभाग के अधिकारियों को काश्तकारो को अधिकारिक जानकारी प्रदान कर लाभांवित करने के निर्देश प्रदान किए। राज्यपाल ने आंगनबाडी केन्द्रों पर बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास तथा बालिकाओं की उपस्थिति एवं पोषण को लेकर विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में पूर्व में इस योजना के लाभ से वंचित लोगों को जोडने के निर्देश दिए। डेयरी विभाग के अधिकारियों को जिले में डेयरी उत्पाद के विकास की संभावनाओ पर कार्य करने पर बल दिया।

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को मनुस्मृति का पूरा ज्ञान था : मायावती

लखनऊ (हिंस)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को मनुस्मृति का पूरा ज्ञान था। उनकी अनुयायी और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इसका पूरा ज्ञान है। तभी इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाकर यहां दु:खी और पीडि़तों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बसपा की स्थापना की गई है, यह भी सर्वविदित है। मायावती ने भाजपा, कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने पोस्ट में कहा है कि कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी पार्टी को उनके राजनैतिक स्वार्थ में, ख़ासकर आरक्षण को लेकर अपने देश के संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे। जरूरत पड़ने पर इसके विरुद्ध बसपा संघर्ष के लिए भी तैयार है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार का आठ वर्षों का शासनकाल, जनता की उम्मीद के हिसाब से पूरे तौर से खरा नहीं उतरा है। कानून-व्यवस्था के मामले में तो स्थिति काफी ज्यादा ख़राब रही है, जिससे जनता काफी दु:खी है। इस ओर सरकार जरूर ध्यान दे।

न्यायालय के आदेश पर कोतवाल, चौकी इंचार्ज समेत आठ पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज

उन्नाव/रायबरेली (हिंस)। कोतवाल, चौकी इंचार्ज समेत आठ पुलिसकर्मियों पर न्यायालय के आदेश पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वर्तमान में ये कोतवाल व चौकी इंचार्ज सहित कई सिपाही रायबरेली में तैनात हैं। मामला 2021 का है जब सभी पुलिस कर्मी उन्नाव के माखी थाने में तैनात थे। मामले की जांच उन्नाव के सफीपुर पुलिस उपाधीक्षक कर रहे हैं। उन्नाव के जुराखन खेड़ा निवासी कमल किशोर ने 30 जुलाई 2021 में जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी कि वह सफीपुर में चकलवंसी से संडीला रोड पर जानवर अस्पताल के पास 24 फरवरी 2021 को अपनी भूमि पर निर्माण करा रहे थे। तत्कालीन माखी थानाध्यक्ष पवन कुमार सोनकर, दारोगा विनोद कुमार, स्वदेश कुमार, दो आरक्षी व एक चालक उनके प्लॉट पर आए और निर्माण रोकने की बात कही। इस पर उन्होंने काम रुकवा दिया। इसका कारण पूछा तो पुलिसकर्मियों ने एसडीएम सफीपुर की ओर से निर्माण रुकवाए जाने का आदेश होने की बात कही। कमल ने याचिका में बताया कि जब उन्होंने लिखित आदेश दिखाए। पुलिसकर्मी कोई लिखित आदेश न होने की बात कहते हुए 50 हजार रुपए की मांग करने लगे। पीड़ित का कहना है कि इसी दौरान कोतवाल की नजर घटना का वीडियो बना रहे उनके पुत्र संकल्प पर पड़ी तो उन्होंने मुझे और बेटे को जमकर पीटा। धमकी दी कि अगर इस घटना के बारे में कहीं शिकायत की तो घर से उठाकर मुठभेड़ दिखाते हुए हत्या करा दूंगा। पुलिसकर्मियों ने उनके पुत्र के मोबाइल से सारा डाटा डिलीट कर दिया और उनके पास पड़े पांच हजार रुपए भी ले लिए। साथ ही उनका व उनके पुत्र का शांतिभंग में चालान कर दिया। मामले को लेकर वर्तमान में डलमऊ के प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सोनकर का कहना है कि आरोपियों का शांतिभंग में चालान किया गया था। इसके अतिरिक्त लगाए गए आरोप निराधार हैं।

आशा वर्करों ने मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय पर किया प्रदर्शन

जींद (हिंस)। आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर सोमवार को आशा वर्कर्स एवं फैसिलिटेटरों ने सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया और तहसीलदार माध्यम से केंद्र सरकार को मांगों को लेकर ज्ञापन भेजा। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला प्रधान नीलम, जिला सचिव राजबाला ने किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में आशा वर्कर्स अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर असांदोलनरत हैं लेकिन उनकी समस्याओं का निदान नही किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पिछले 12 वर्ष से आशा की प्रोत्साहन राशि में कोई बढ़ोत्तरी नही की गई है आशाओं के काम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बढ़ा रही है। आशा वर्कर से फील्ड में स्वास्थ्य से संबंधित सारे कार्यों को करते हुए उनका रखरखाव रखने का दबाव बनाया जाता है। अब तो सरकार ने हद ही कर दी है आशा वर्कर्स को बिना कोई प्रोत्साहन राशि दिए डिजिटल कार्य भी करवा रही है। जिस देश की तमाम 10 लाख आशा वर्कर्स बहुत परेशान हैं। उन्होंने मांग की कि एनएचएम को स्थायी प्रोग्राम बनाकर आशा वर्कर को पक्का कर्मचारी बनाया जाए। जब तक पक्का कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक 45वें 46 वें श्रम सम्मेलन की सिफारिश को लागू करते हुए आशाओं को न्यूनतम वेतन 26 हजार दिया जाए। पूरे देश में एक समान कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित कि जाएं। छह माह का सवेतन मातृत्व अवकाश, 20 दिन का आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश सुनिश्चित किया जाए। पेंशन तक कोई सेवानिवृत्ति नही की जाए। आशा कार्यकर्ताओं की वरिष्ठता के आधार पर अन्य पदों पर पदोन्नति सुनिश्चित कि जाएं। सभी पीएचसी, सीएचसी और अस्पतालों में आशा विश्राम कक्ष बनाए जाएं। आशा कार्यकर्ताओं को स्कूटर दिया जाए तथा ड्यूटी के लिए यात्रा व्यय का भुगतान किया जाए। डिजिटलीकरण के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले टैबलेट, डेटा पैक, नेटवर्क और प्रशिक्षण उपलब्ध करवाई जाए। सभी तरह के ऑनलाइन काम के आशा वर्कर्स को इंसेंटिव दिए जाएं।

नाबालिगों को तलाश नहीं करने पर चार एसपी तलब

जयपुर (हिंस)। राजस्थान हाईकोर्ट ने चार अलग-अलग मामलों में नाबालिगों की तलाश नहीं होने पर चार जिला पुलिस अधीक्षकों को तलब किया हैं। अदालत ने बारां और धौलपुर पुलिस अधीक्षक को 7 अप्रेल, झुंझुनूं एसपी को 8 अप्रैल और डीग एसपी को 9 अप्रैल को तलब किया है। अदालत ने सभी जिला एसपी से मामलों से जुडी प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जस्टिस नरेंद्र सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश लापताओं के परिजनों की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर अलग-अलग सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में बारां जिले के हरनावदाशाहजी और झुंझुनूं जिले के गुढ़ा गौडजी थाना क्षेत्र से गायब नाबालिग बालिकाओं को तलाशने के लिए पुलिस को निर्देश देने की गुहार की गई थी। वहीं धौलपुर जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र से करीब डेढ़ साल पहले गायब हुए 11 साल के दिव्यांग आकाश की तलाश नहीं होने पर परिजनों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान सभी मामलों में पुलिस थानों ने अभी तक की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश

की थी। रिपोर्ट के साथ थानाधिकारी भी कोर्ट में मौजूद रहे, लेकिन कोर्ट पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि नाबालिगों को तलाशने में पुलिस की ढिलाई रही हैं। ऐसे में संबंधित पुलिस अधीक्षक कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें। मामले में बारां जिले के हरनावदाशाहजी थाने की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार बालिका 24 दिसंबर 2024 को अपने घर से गायब हुई थी। घटना के समय बालिका की उम्र 17 साल 6 महीने थी। बालिका के पिता ने छीपाबड़ौद के ढोलम थाने के नितेश नागर पर उसकी पुत्री को बहलाकर ले जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बालिका को कोटा, झालावाड़, जयपुर और अन्य जगह तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। घटना के बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी देखी गई, लेकिन दोनों उसमें कहीं भी दिखाई नहीं दिए। आरोपी का फोन भी बंद है। दोनों के आधार कार्ड पर कोई सिम भी एक्टिवेट नहीं हुई। दूसरे मामले में झुंझुनूं जिले के गुढ़ागौडजी थाने की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग बालिका 19 फरवरी 2025 से गायब हैं। घटना के समय बालिका की उम्र 16 साल 9 माह थी। परिजनों ने गोदारो का बास सिंग्नोर निवासी योगेश सिंह पर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि आरोपी देर रात घर के बाहर आया और बालिका को लेकर चला गया। हमने उनका पीछा भी किया, लेकिन वो फरार हो गया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट नें कहा कि हमने आरोपी के परिजनों से भी पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं होना बताया। दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर संदिग्धों से भी पूछताछ की। बालिका की तलाश के लिए गांधीधाम गुजरात, जयपुर और उदयपुर में भी कार्रवाई की गई, लेकिन बालिका को अभी तक तलाश नहीं किया जा सका। धौलपुर जिले के पुलिस थाना बाड़ी से करीब डेढ़ साल पहले गायब हुए 11 साल के दिव्यांग बालक की तलाश पुलिस अभी नहीं कर पाई हैं। पुलिस की ओर से हाईकोर्ट में दायर तथ्यात्मक रिपोर्ट में पुलिस का कहना है कि 15 जून 2023 से लापता बालक की तलाश के लिए हमने 25 हजार के ईनाम की भी घोषणा की हैं। बालक की तलाश में पुलिस टीमें धौलपुर जिले, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में भेजी गई। बालक की तलाश के लिए उसके पोस्टर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर चस्पा किए गए। होटल, ढाबों पर बालक की तलाश की गई। पिछले साल 31 दिसंबर 2024 को बालक के पीवीसी कार्ड के लिए 50 रुपए का भुगतान हुआ। यह भुगतान किस बैंक, खाते अथवा ऑनलाइन ऐप के जरिए किया गया। उसकी जानकारी के लिए यूआईडीएआई रीजनल ऑफिस, दिल्ली को लिखा गया, लेकिन उन्होंने बिना हाईकोर्ट के आदेश के जानकारी देने से मना कर दिया।

जिले के टॉप टेन अपराधियों में शुमार मो. खुर्शीद गिरफ्तार

अररिया (हिंस)। एसपीए अंजनी कुमार के निर्देश पर जिले में फरार वारंटियों के साथ कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में फारबिसगंज थाना पुलिस ने जिले के टॉप टेन अपराधियों में शुमार थाना क्षेत्र के कुड़ैली के रहने वाले मो. खुर्शीद पिता मो. रियाजउद्दीन को गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह को मिली गुप्त सूचना के तहत फारबिसगंज थाना पुलिस ने खुर्शीद को गिरफ्तार किया। मो.खुर्शीद के खिलाफ केवल फारबिसगंज थाना में 14, जोगबनी रेल थाना में एक संगीन मामलों में मामला दर्ज हैं। पुलिस को इनकी लंबे समय से तलाश थी। इनकी गिरफ्तारी को लेकर कई बार पुलिस की छापेमारी हुई। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही खुर्शीद फरार हो जाता था और आखिरकार फारबिसगंज थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इस बात की जानकारी थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह ने दी। गिरफ्तार कुख्यात मो. खुर्शीद को सोमवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी पर फारबिसगंज थाना के कई मामला में वांछित था। गिरफ्तार मो. खुर्शीद के खिलाफ कई इश्तिहार एवं कुर्की लंबित है। यह पूर्व से कई लूट, डकैती एवं आर्म्स एक्ट के कांड में आरोपी रहा है। छापामारी टीम में थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक राघवेंद्र कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक राजनंदनी सिंहा, प्रीति कुमारी, राजाबाबू एवं थाना सशस्त्र बल के जवान मौजूद थे।

पीएम आवास योजना के तहत 75, 295 परिवारों को 40, 000 रुपए की पहली किस्त जारी

पटना (हिंस)। बिहार सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय में सोमवार को विभागीय मंत्री श्रवण कुमार ने ग्रामीण क्षेत्र के 75, 295 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए 40, 000 रुपए की पहली किस्त जारी की। इसके तहत 75, 295 लाभार्थियों के लिए प्रथम किस्त की सहायता राशि 301.18 करोड़ रुपए जारी किया गया। इस मौके पर मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार में 7, 24, 230 परिवारों को आवास की स्वीकृति हुई है। अब तक 6, 300, 49 लाभार्थियों को आवास योजना की प्रथम किस्त जारी कर दी गई है। जबकि तीनों किस्त अब तक 1, 21, 539 लाभार्थियों को जारी कर दी गई है। अब तक 50, 409 आवास पूर्ण हो गए हैं। आज 75, 295 लाभार्थियों को आवास योजना का प्रथम किस्त जारी किया गया है। समय-समय पर और दो किस्त जारी कर दिया जाएगा। आवास योजना के तहत कुल 1.20 लख रुपए की तीन किस्त में राशि आवास निर्माण की प्रगति के साथ दी जाती है। प्रथम किस्त जारी होने के 100 दिनों के भीतर आवास निर्माण की प्रगति के आधार पर दोनों की जारी कर दिए जाएंगे। मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि इसके अलावा लाभार्थियों को मनरेगा के माध्यम से 90 दिनों के कुशल मजदूरी के रूप में 22, 050 रुपए भी दिए जाते हैं। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत इन आवासों में शौचालय निर्माण के लिए अलग से 12, 000 की सहायता राशि भी दी जाती है। इसके लिए विभाग की ओर से स्क्रीनिंग चल रही है और अब तक आवास योजना के लिए 52 लाख 80 हजार लोगों का नाम शामिल हुआ है।

पंजाब के मंत्री खुड्डिया को नही मिली विदेश जाने की इजाजत

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब के कृषिमंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को केंद्र सरकार ने विदेश जाने की अनुमति नही दी है। मंत्री खुड्डियां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल को 29 मार्च से 6 अप्रैल तक अमेरिका जाना था। यह सरकारी दौरा था। इसका उद्देश्य डेयरी विभाग के कामकाज के लिए अध्ययन करना था ताकि पंजाब में डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके। मंत्री के अनुसार उनके साथ कई विभागीय अधिकारी भी विदेश जाने वाले थे। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ केंद्र को इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। उसे विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया। खुड्डियां के अनुसार अब केंद्र से दोबारा बातचीत की जाएगी, क्योकि विदेश जाने की अनुमति खरिज करने को लेकर कोई ठोस कारण नही दिया गया है।

योगी सरकार के आठ साल में बिछने लगा उद्योगों का जाल

योगी से पूर्व की सरकार में महज 29.33 करोड़ रुपए का हुआ था औद्योगिक निवेश

गोरखपुर (हिंस)। योगी सरकार के आठ साल में माहौल बदलने का असर क्या है, इसका एक बड़ा सटीक जवाव आपको आज के गोरखपुर को देखकर मिल जाएगा। लंबे दौर तक पहचान को जूझता रहा यह जिला अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी के मामले में मजबूत होकर औद्योगिक नक्शे पर भी चमक गया है। जिस जिले से उद्यमियों ने मुंह फेर लिया था, वहां 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से औद्योगिक प्रगति का ऐसा माहौल बनना शुरू हुआ कि देश की बड़ी-बड़ी कंपनियां, यहां तक कि मल्टीनेशनल भी इंडस्ट्री लगा रही हैं। बदलाव के इन आठ सालों (2017 से 2025 तक) में गोरखपुर को 319 औद्योगिक इकाइयों के सापेक्ष 11618.75 करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश प्राप्त हुआ जिससे 39, 448 लोगों के रोजगार का मार्ग प्रशस्त हुआ। जबकि योगी सरकार के पहले 2012 से 2017 तक औद्योगिक

निवेश दो यूनिट्स के सापेक्ष महज 29.33 करोड़ रुपए और इसके जरिए रोजगार की संख्या मात्र 307 थी। औद्योगिक विकास और गोरखपुर के बीच दशकों तक विरोधाभासी रिश्ता बना रहा लेकिन आठ साल पहले योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद माहौल ऐसा बदला कि अब दोनों एक दूसरे के पूरक रूप में देखे जा रहे हैं। जिस गोरखपुर में स्थानीय पूंजीपति भी औद्योगिक निवेश करने से घबराते थे, अब वहां देश की नामी कंपनियों के आने की हो? सी दिखती है। गोरखपुर को औद्योगिक विकास के नक्शे पर स्थापित करने के लिए नोएडा की तर्ज पर गीड़ा (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) की स्थापना यूं तो साढ़े तीन दशक पहले ही कर दी गई थी लेकिन नोएडा से प्रतिस्पर्धा का दौर बीते आठ सालों में शुरू हुआ है। योगी सरकार के आठ साल के कार्यकाल में गोरखपुर के विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र गीड़ा में मल्टीनेशनल समेत कई ऐसी बड़ी यूनिट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ जो पहले सिर्फ कल्पनाओं की बात होती थीं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 2017 के पहले तक लचर कानून व्यवस्था, सुविधाओं के घोर अभाव और सरकारों के उदासीन रवैए से गीड़ा में निवेश, दूर की कौड़ी लगती थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों और उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी देने का अनवरत ऐलान किया, इंडस्ट्री फ्रेंडली नीतियां बनाईं तो गीड़ा भी निवेश के लिए लिए बेहतरीन गंतव्य बन गया है। पहले जहां सालों कोई मुख्यमंत्री गीड़ा झांकने तक नहीं आता था, वहीं बतौर मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ हर साल छह-सात बार गीड़ा आकर उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हैं।

सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में मामूली गिरावट, चांदी की बढ़ी चमक

नई दिल्ली

घरेलू सर्राफा बाजार में सोने के भाव में मामूली गिरावट का रुख नजर आ रहा है। देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 89,770 रुपये से लेकर 89,970 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है।

इसी तरह 22 कैरेट सोना 82,290 रुपये से लेकर 82,440 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। सोना के विपरीत चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई है, जिसके कारण दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी 1,00,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है।

देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 89,970 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 82,440 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 89,770 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 82,290 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 89,870 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 82,340 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना 89,770 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 82,290 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 89,770 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 82,290 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 89,970 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 82,440 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

वहीं पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 89,870 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 82,340 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह जयपुर में 24 कैरेट सोना 89,970 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 82,440 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी सोना के भाव में मामूली गिरावट आई है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 89,770 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

इसी तरह इन तीनों शहरों के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 82,290 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

न्यूज ब्रीफ

केयर हेल्थ इंश्योरेंस को 104 करोड़ का मांग नोटिस

नई दिल्ली। रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) ने सोमवार को कहा कि उसकी अनुषंगी कंपनी केयर हेल्थ इंश्योरेंस को आकलन वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए 104.77 करोड़ रुपये का मांग नोटिस मिला है। आरईएल ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि मांग नोटिस मुंबई के सेंट्रल सर्किल 6(2) स्थित सहायक आयकर आयुक्त के कार्यालय द्वारा भेजा गया है। कंपनी सूचना के अनुसार केयर हेल्थ इंश्योरेंस की वित्तीय स्थिति कंपनी के साथ जुड़ी है। यदि आयकर की मांग का भुगतान करना आवश्यक है, तो इसका भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। साथ ही कर सलाहकारों की सलाह के आधार पर केयर हेल्थ निर्धारित समय सीमा के भीतर उचित मंच के समक्ष उक्त नोटिस खिलाफ अपील दायर करेगी।

अमेजन 300 रुपये से कम कीमत वाले उत्पादों पर नहीं लेगा 'रेफरल' शुल्क

नई दिल्ली। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने सोमवार को 300 रुपये से कम कीमत वाले 1.2 करोड़ से अधिक उत्पादों पर रेफरल शुल्क नहीं लेने की घोषणा की। यह नया कदम उसके मंच के विक्रेताओं के लिए एक बड़ी बदलाव की ओर पहुंचाएगा। रेफरल शुल्क एक प्रकार का कमीशन है जो विक्रेता प्रत्येक बेचे गए उत्पाद के लिए अमेजन को देते हैं। अमेजन इंडिया के एक प्रमुख अधिकारी ने कहा कि इस कदम से हम विक्रेताओं के लिए अमेजन डॉट इन पर बिक्री को और अधिक आकर्षक बना रहे हैं। यह पहल अमेजन पर विक्रेताओं की वृद्धि का समर्थन करेगा। इस नए नीति के अनुसार, शून्य रेफरल शुल्क की सुविधा 135 उत्पाद श्रेणियों में लागू होगी, जिसमें परिधान, फैशन आभूषण, घरेलू सजावट, सौंदर्य प्रसाधन, रसोई उत्पाद, और पालतू पशु उत्पाद आदि शामिल हैं। इसके अलावा, अमेजन ने विक्रेताओं के लिए नई फ्लैट दर और बाहरी पूर्ति सेवाओं का भी बदलाव किया है। इसमें एक हिस्सा राष्ट्रीय शिपिंग दरों में भी कटौती का हिस्सा है, जिससे विक्रेताओं को अधिक लाभ होगा। इसके साथ हल्के सामानों पर हैंडलिंग शुल्क में भी कटौती की गई है। यह बदलाव अमेजन इंडिया की बाजार में विक्रेताओं को नया उत्साह देगा।

एपीडा ने सिक्किम से सोलोमन द्वीप तक जीआई-टैग वाली डैले मिर्च के निर्यात को सुगम बनाया

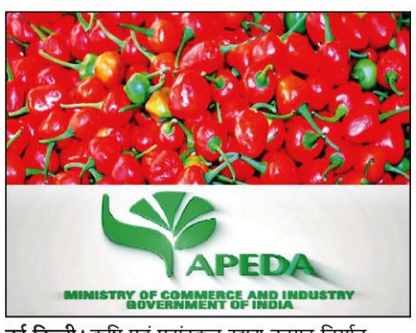

नई दिल्ली। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने सिक्किम से सोलोमन द्वीप तक जीआई-टैग वाली डैले मिर्च की पहली खेप का सफलतापूर्वक निर्यात किया है। जीआई-टैग वाली 15,000 किलोग्राम डैले मिर्च के निर्यात से सिक्किम में किसानों की आय में वृद्धि हुई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में बताया कि सिक्किम से सोलोमन द्वीप तक जीआई-टैग वाली डैले मिर्च की पहली खेप का एपीडा ने सफलतापूर्वक निर्यात किया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि वैश्विक जैविक कृषि बाजार में भारत की बढ़ती प्रमुखता को चिह्नित करती है और पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्रीमियम उत्पादों की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मांग को उजागर करती है। खरीद के संदर्भ में अपने व्यापक नेटवर्क के जरिए दक्षिण सिक्किम के किसानों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) से लगभग 15,000 किलोग्राम ताजा डैले मिर्च प्राप्त की, जिसमें टिंकिटम और तारकू क्षेत्र शामिल हैं। इस खेप ने सुनिश्चित किया कि किसानों को सामान्य 180-200 रुपये प्रति किलोग्राम की तुलना में 250-300 रुपये प्रति किलोग्राम का प्रीमियम मूल्य मिले, जिससे जीआई टैगिंग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आर्थिक लाभों की पुष्टि हुई।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत, एशिया में बिकवाली का दबाव

नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहे थे। डाउ जॉन्स फ्यूचर्स भी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर, यूरोपीय बाजारों में पिछले सत्र के दौरान लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा। एशियाई बाजारों में भी आमतौर पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है।

अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान निचले स्तर से रिकवरी होने की वजह से वॉल स्ट्रीट के सूचकांक मजबूती के साथ बंद होने में सफल रहे। एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.08 प्रतिशत की तेजी के साथ 5,667.56 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 0.52 प्रतिशत उछल कर 17,784.05 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। डाउ जॉन्स फ्यूचर्स फिलहाल 202.84 अंक यानी 0.48 प्रतिशत की मजबूती के साथ 42,188.19 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

अमेरिका के विपरीत यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के दौरान दबाव में कारोबार करने के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। एफटीएसई इंडेक्स 0.64 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 8,646.79 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने भी 0.64 प्रतिशत टूट कर 8,042.95 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 107.47 अंक यानी 0.47 प्रतिशत लुढ़क कर 22,891.68 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

एशियाई बाजार में आमतौर पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है। एशिया के 9 बाजारों में से 7 के सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि सिर्फ 2 सूचकांक बढ़त के साथ हरे निशान में बने हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी 0.32 प्रतिशत की तेजी के साथ 23,502 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.13 प्रतिशत उछल कर 3,931.64 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है।

दूसरी ओर, निक्केई इंडेक्स 0.06 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 37,656.08 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह कोस्पी इंडेक्स 0.13 प्रतिशत लुढ़क कर 2,639.65 अंक तक गिर गया है। जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल यह सूचकांक 144.83 अंक यानी 2.37 प्रतिशत टूट कर 6,113.35 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

इसी तरह हैंग सेंग इंडेक्स 0.28 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,623.98 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा ताईवान वेटेड इंडेक्स 0.25 प्रतिशत फिसल कर 22,152.96 अंक के स्तर पर, शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.25 प्रतिशत लुढ़क कर 3,356.50 अंक के स्तर पर और सेट कंपोजिट इंडेक्स 0.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,186.17 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

टेनसेंट ने अपने एआई मॉडल का नया वर्जन लांच किया

नई दिल्ली। चीन की सबसे वैल्यूएबल टेक कंपनी टेनसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का नया वर्जन लॉन्च किया है। यह निर्णय चीन की भीड़भाड़ वाली एआई कंपनी में लीडरशिप हासिल करने की दिशा में लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह नया मॉडल डीपसीक की आर 1 तकनीक की तरह काम करता है, जिसने कम लागत और कम कंप्यूटिंग पॉवर में ओपन एआई और मेटा जैसे दिग्गजों के मॉडल को टक्कर दी थी। टेंसेंट का यह नया एआई मॉडल उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे कंपनी चीन में एआई सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। टेक कंपनी ने एक ऑनलाइन इवेंट में दावा किया है कि उसका नया एआई मॉडल टी1 ताजा तकनीक से लैस है और इसमें लॉजिक व राइटिंग क्षमता बेहतरीन है। टेनसेंट इंजीनियर्स ने कहा कि टी1 का प्रदर्शन ओपनी एआई के1 और क्रा जैसे टॉप मॉडल्स के बराबर है। कंपनी का दावा है कि उसका मॉडल आर1 जितना ही दमदार है लेकिन कीमत में आधा है। इससे पहले बायडू ने डीपसीक का मॉडल अपने सर्च इंजन और मैप्स में भी शामिल किया था।

महिंद्रा का वाहनों की कीमतें 3 प्रतिशत बढाने का ऐलान

मुंबई

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी एसयूवी और कमर्शियल वाहनों की पूरी रेंज की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया। कंपनी द्वारा वाहनों की कीमतों में 3 प्रतिशत तक बढोत्तरी की जाएगी। कंपनी ने बताया कि नई कीमतें अप्रैल 2025 से लागू होंगी। इसकी वजह इनपुट लागत और कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी होना है। एमएंडएम की ओर से कहा गया कि बढ़ी हुई लागत को काफी हद तक वहन करने की कोशिश की गई, लेकिन अब इसके एक हिस्से को ग्राहकों को पास करना जरूरी हो गया था। कंपनी ने आधिकारिक बयान में कहा कि कीमतों में वृद्धि एसयूवी और कमर्शियल वाहनों के अलग-अलग मॉडल पर आधारित है। कंपनी ने हाल ही में ऐलान किया था कि फरवरी महीने में उसकी कुल ऑटो बिक्री निर्यात सहित 83,702 यूनिट्स रही है। यूटिलिटी व्हीकल्स सेगमेंट में, महिंद्रा ने घरेलू बाजार में 50,420 एसयूवी बेचीं और निर्यात सहित कुल 52,386 वाहन बेचे। वाणिज्यिक वाहनों की घरेलू बिक्री 23,826 यूनिट्स रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रैक्टर की बिक्री में भी फरवरी में उछाल देखा गया। फरवरी 2025 में घरेलू स्तर पर ट्रैक्टर की बिक्री 23,880 यूनिट्स रही, जो कि फरवरी 2024 में हुई 20,121 यूनिट्स की बिक्री से अधिक थी। कंपनी ने फरवरी 2025 में 1,647 ट्रैक्टर का निर्यात किया है, जिसके कारण कुल ट्रैक्टर बिक्री 25,527 यूनिट्स रही है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 21,672 यूनिट्स थी।

जेप्टो ने बढ़ाया ग्रोसरी डिलीवरी का जलवा

नई दिल्ली। भारतीय क्विक कॉमर्स कंपनी, जेप्टो, अब प्लान्ड ग्रोसरी डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ा रही है। कंपनी की योजना घरों में उच्च स्तर का किराना सामान पहुंचाने की है। यह नई रणनीति को शुरू करने के माध्यम से जेप्टो की उम्मीद है कि बिग बास्केट के बाजार में भी मान्यता प्राप्त करेगा। जेप्टो ने इस सेगमेंट में अपनी पहचान बनाने के लिए सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। सुपर-सेवर जैसे प्रोग्राम में भारी डिस्काउंट और नए मॉडल जैसे मार्जिन और आय में सुधार का भाव है। जेप्टो की अगली नई स्ट्रैटेजी में विश्वस्त युक्तिगत उपाय हैं, जिसमें मंथली ग्रोसरी ऑर्डर या मेंबरशिप सर्विस को ध्यान में रखा गया है और जल्दी और आसानी से किराना सामान डिलीवरी के माध्यम से कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना है। जेप्टो की यह पहल ने बाजार में फिर उत्साह भर दिया है।

हैम्लिटन में हैरीटेज कोन 17 इवेंट में रखीं कार

हैम्लिटन में हैरीटेज कोन 17 इवेंट में रखीं कार के मॉडल्स की तस्वीरें खींचते हुए एक व्यक्ति।

डीजीसीए का एयरलाइन कंपनियों से यात्रियों की जानकारी एसएमएस के जरिए साझा करने का निर्देश

नई दिल्ली

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों को नए और सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत उन्हें यात्रियों को उनके अधिकारों के बारे में बताना होगा। डीजीसीए ने यह कदम यात्रियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए उठाया है।

डीजीसीए ने जारी आदेश में सभी एयरलाइनों को टिकट बुक होने के बाद एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध यात्री चार्टर का लिंक भेजना अनिवार्य है। नियामक ने एयरलाइन कंपनियों को एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए यात्रियों को उनके अधिकारों की जानकारी देने का भी निर्देश दिया है। नियामक ने एयरलाइनों से कहा कि वे टिकट बुक होने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर उपलब्ध यात्री चार्टर का ऑनलाइन लिंक यात्री को संदेश (एसएमएस/व्हाट्सएप) के रूप में भेजें।

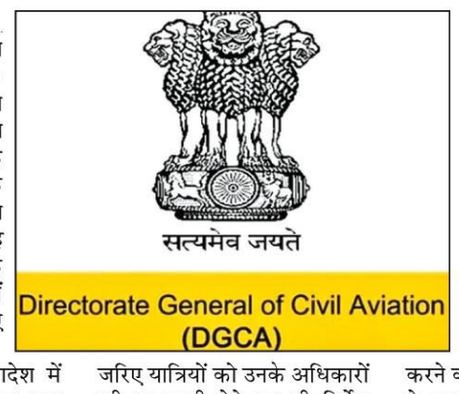

डीजीसीए ने एयरलाइनों को निर्देश दिया है कि वे यात्रियों को हवाई टिकट के साथ उनके अधिकारों का लिंक भी उपलब्ध कराएं।

इसके अलावा डीजीसीए ने भारतीय एयरलाइनों को यात्रियों को देरी, रद्दीकरण, बोर्डिंग से इनकार और सामान संबंधी मुद्दों के बारे में उनके अधिकारों के बारे में सूचित करने का आदेश दिया है। नियामक ने एयरलाइनों को एसएमएस, व्हाट्सएप, टिकट और अपनी वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन यात्री चार्टर का लिंक साझा करने को कहा है। हालांकि, इंडिगो ने पहले ही इस निर्देश को लागू करना शुरू कर दिया है।

जल्द लांच होगा नया फोन वीवो वाय 39 5जी

नई दिल्ली

भारतीय बाजार में चायनीज कंपनी वीवो जल्द ही अपना नया फोन वीवो वाय39 5जी लॉन्च करेगी। हालांकि, कंपनी ने अभी आधिकारिक लॉन्च डेट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हाल ही में लीक हुई जानकारी से इसके फीचर्स और संभावित कीमत का खुलासा हुआ है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीवो वाय39 5जी भारत में दो वेरिएंट में आ सकता है। पहला वेरिएंट 8जीबी रैम प्लस 128जीबी स्टोरेज के साथ होगा, जिसकी संभावित कीमत रुपए 16,999 हो सकती है। वहीं, 8जीबी रैम प्लस 256जीबी स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत रुपए 18,999 रहने की उम्मीद है। फोन दो कलर ऑप्शन—ओशन ब्लू और लोटस पर्पल में लॉन्च हो सकता है। फोन में 6.68 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दिया जाएगा, जो 720 गुणा 1608 पिक्सल रेजोल्यूशन और 120एचझेड रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स होगी। इस डिवाइस में स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 चिपसेट दिया जाएगा, जिससे फोन की परफॉर्मेंस दमदार होगी। फोन की सबसे खास बात इसकी 6500 एमएएच बैटरी होगी, जो 44डब्ल्यू फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

इसके अलावा, इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और आईपी64 रेटिंग भी होगी। वीवो वाय39 5जी के इंडियन और ग्लोबल वेरिएंट में कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। फोन एंड्रॉइड 15 पर आधारित फनटच ओएस 15 पर चलेगा। भारतीय ग्राहकों को अब इसके आधिकारिक लॉन्च का इंतजार है। कैमरे की बात करें तो इसके रियर में 50एमपी का प्राइमरी सेंसर और 2 एमपी का बोकेह लेंस मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8 एमपी का फ्रंट कैमरा हो सकता है।

सैमसंग के 3 स्मार्टफोन मिल रहे कम बजट में

नई दिल्ली। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी सैमसंग के 3 स्मार्टफोन कम बजट में मिल रहे है। इन स्मार्टफोन्स की कीमत रुपए 7,499 से शुरू होती है और इनमें दमदार बैटरी, बड़ा डिस्प्ले और शानदार कैमरा मिलता है। खास बात यह है कि ये फोन रैम प्लस फीचर के साथ आते हैं, जिससे रैम को 12जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। सैमसंग गैलेक्सी एम 05 सबसे किफायती मॉडल है, जिसकी कीमत रुपए 7,499 रखी गई है। यह 4जीबी रैम और 64जीबी स्टोरेज के साथ आता है, जिसे रैम प्लस फीचर से 8जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 6.7-इंच एचडी प्लस डिस्प्ले और 50एमपी प्राइमरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 8एमपी का फ्रंट कैमरा है। फोन की बैटरी 5000एमएएच की है, जो 25डब्ल्यू फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सैमसंग गैलेक्सी एम 05 की कीमत रुपए 8,599 है और यह 6जीबीरैम और 128जीबी स्टोरेज के साथ आता है। इसमें मीडियाटेक हेलियो जी85 प्रोसेसर दिया गया है। फोन का 6.7-इंच डिस्प्ले 60 एचझेड रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। सैमसंग गैलेक्सी एम 06 5जी की कीमत रुपए 9,199 है। यह फोन डायमेंसिटी 6300 चिपसेट के साथ आता है और 12 5जी बैंड को सपोर्ट करता है। इसमें 4 जीबी रैम प्लस 128जीबी स्टोरेज है, जिसे रैम प्लस से बढ़ाया जा सकता है।

हरिद्वार में हुआ युवा ऑल स्टार्स चैम्पियनशिप ट्रॉफी का भव्य अनावरण

हरिद्वार

कबड्डी के स्वर्णिम इतिहास और इसकी जड़ों से प्रेरणा लेते हुए युवा ऑल स्टार्स चैम्पियनशिप ट्रॉफी का भव्य अनावरण हरिद्वार में किया गया। इस ऐतिहासिक क्षण के दौरान खेल जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रहीं, जिन्होंने इस आयोजन को खास बना दिया।

इस विशेष अवसर पर भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के पूर्व महासचिव और वर्तमान में एशियाई फेंसिंग परिसंघ के महासचिव राजीव मेहता, उत्तराखंड कबड्डी संघ के अध्यक्ष महेश जोशी, सचिव चेतन जोशी और उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डी.के.सिंह सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

युवा ऑल स्टार्स चैम्पियनशिप के सीईओ विकास गौतम ने ट्रॉफी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, इस ट्रॉफी का उद्देश्य न केवल विजेताओं को सम्मानित करना है, बल्कि युवा पीढ़ी को कबड्डी के गौरवशाली अतीत से भी जोड़ना है। ट्रॉफी को ऐसे तत्वों से तैयार किया गया है, जो कबड्डी की सदियों पुरानी यात्रा और इसकी सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कबड्डी का उल्लेख महाभारत तक में मिलता है और यह खेल सदियों से मिट्टी के मैदानों पर ही विकसित हुआ है। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को सम्मान देते हुए, ट्रॉफी के आधार को तमिलनाडु के नागमलाई पुदुकोट्टई से लाई गई मिट्टी से बनाया गया है, जिसका इस खेल के इतिहास में विशेष महत्व है।

इसके अलावा, ट्रॉफी के केंद्र में मौजूद खंभा मजबूती और निरंतर प्रगति का प्रतीक है, जबकि चारों ओर लगी लकड़ी जीवन और विकास का संकेत देती है। ट्रॉफी के शीर्ष पर रखी गई कबड्डी मैट, खेल के पारंपरिक मिट्टी के मैदानों से आधुनिक मैट तक की यात्रा को दर्शाती है। इस भव्य अनावरण समारोह में देशभर से युवा खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, स्कूली छात्रों और खेल अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। युवा ऑल स्टार्स चैम्पियनशिप न सिर्फ युवा प्रतिभाओं को निखारने का मंच है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक मजबूत कदम भी है। कबड्डी की जड़ों से जुड़कर इसे भविष्य की ऊंचाइयों तक ले जाने के इस प्रयास को खिलाड़ियों और खेलप्रेमियों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। युवा ऑल स्टार्स चैम्पियनशिप भारतीय कबड्डी के भविष्य को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी का अनावरण इसी सुनहरे सफर की एक झलक है।

न्यूज ब्रीफ

बीसीसीआई ने महिला टीम के लिए केंद्रीय अनुबंध की घोषणा की, हरमनप्रीत, स्मृति ग्रेड ए में

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोमवार को महिला क्रिकेट टीम की केंद्रीय अनुबंध सूची की घोषणा की, जिसमें तीन प्रमुख खिलाड़ियों को ग्रेड ए में बरकरार रखा गया है। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, उप-कप्तान स्मृति मंधाना और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को बीसीसीआई ने एक बार फिर शीर्ष श्रेणी में बनाए रखा है। बीसीसीआई द्वारा जारी इस सूची में कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया है, जबकि कुछ खिलाड़ियों को अनुबंध से बाहर कर दिया गया है। उमा छेत्री, अरुंधति रेड्डी, तितास साधु और श्रेयंका पाटिल को पहली बार केंद्रीय अनुबंध सूची में जगह दी गई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड युवा खिलाड़ियों पर भी भरोसा जता रहा है। दूसरी ओर राजेश्वरी गायकवाड़, जिन्होंने भारत के लिए आखिरी बार जुलाई 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला था, इस बार अनुबंध सूची में जगह नहीं बना पाईं। ग्रेड बी में इस बार केवल चार खिलाड़ी हैं, जो पिछले साल की तुलना में संख्या में कमी को दर्शाता है। बीसीसीआई केंद्रीय अनुबंध सूची (महिला टीम) ग्रेड ए: हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा। ग्रेड बी: रेणुका ठाकुर, जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, ऋचा घोष। ग्रेड सी: अमनजोत कौर, उमा छेत्री, पूजा वस्त्राकर, अरुंधति रेड्डी, स्नेह राणा, तितास साधु, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, यास्तिका भाटिया।

आईपीएल 2025: चेन्नई में रचिन रविंद्र ने देखा एमएस धोनी के फैंस का जुनून

चेन्नई। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के सलामी बल्लेबाज रचिन रविंद्र ने पहली बार चेन्नई में एमएस धोनी के फैंस का जबरदस्त उत्साह महसूस किया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में जब सीएसकेको जीत के लिए चार रनों की जरूरत थी, तो पूरा चेपॉक स्टेडियम धोनी के छक्के का इंतजार कर रहा था। लेकिन इस बार यह मौका रविंद्र ने ले लिया और डीप मिडविकेट के ऊपर छक्का लगाकर टीम को चार विकेट से जीत दिलाई। मैच के बाद रविंद्र ने कहा, जब आप मैदान पर होते हैं, तो सिर्फ मैच जीतने पर ध्यान होता है, लेकिन इस माहौल को नजरअंदाज करना मुश्किल था। जब धोनी मैदान में आते हैं, तो स्टेडियम में गूंजते सीटी और शोर को महसूस किया जा सकता है। उनके साथ क्रीज साझा करना मेरे लिए बेहद खास था। धोनी की फिनिशिंग का इंतजार कर रहे थे फैंस रविंद्र ने स्वीकार किया कि स्टेडियम में मौजूद फैंस चाहते थे कि वह धोनी को स्ट्राइक दें और वह अपने स्टाइल में मैच खत्म करें। उन्होंने कहा, सभी चाहते थे कि मैं उन्हें स्ट्राइक दूं और धोनी मैच खत्म करें। उन्होंने सीएसकेके लिए कई मैच फिनिश किए हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन मेरे लिए जरूरी था कि मैं टीम को जीत तक पहुंचाऊं। सीएसकेमें सलामी बल्लेबाज के रूप में मौका आईपीएल 2024 में डेवोन कॉनवे की चोट के कारण रविंद्र को पारी की शुरुआत करने का मौका मिला था। इस सीजन की नीलामी में सीएसकेने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल कर रविंद्र को फिर से अपनी टीम में शामिल किया और बतौर ओपनर मौका दिया।

पीजीडीएवी कॉलेज ने 25 साल बाद जीता दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज फुटबॉल का खिताब

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजीडीएवी कॉलेज ने इतिहास रचते हुए 25 साल बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप पर कब्जा जमा लिया। रोमांचक फाइनल में पीजीडीएवी ने पिछले चैंपियन हिंदू कॉलेज को टाई-ब्रेकर में 4-3 से हराकर खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम की ओर से आर्यन कर्की, प्रशांत भंडारी, यश भारद्वाज और अनुराग रावत ने गोल दागे। पीजीडीएवी कॉलेज की प्रिंसिपल, प्रो. कृष्णा शर्मा ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि टीम भविष्य में भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन जारी रखेगी। अंतर-कॉलेज फुटबॉल टूर्नामेंट समिति के संयोजक डॉ. मनोज राठी के अनुसार श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ने तीसरा स्थान हासिल किया।

नानजिंग में वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप का समापन डेविन चार्लटन ने 60 मीटर हर्डल्स में खिताब बरकरार रखा

नानजिंग

बहामास की डेविन चार्लटन ने 60 मीटर हर्डल्स का खिताब बरकरार रखते हुए शानदार प्रदर्शन किया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पुरुषों और महिलाओं की 4×400 मीटर रिले में दबदबा बनाया। इसी के साथ रविवार को 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप का समापन हुआ। अमेरिका ने कुल 6 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। नॉर्वे तीन स्वर्ण के साथ दूसरे और इथियोपिया दो स्वर्ण व तीन रजत के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

चार्लटन की रोमांचक जीत

चार्लटन ने 7.72 सेकंड में दौड़ पूरी कर रोमांचक जीत दर्ज की। यह रेस ऐतिहासिक रही क्योंकि पहली बार छह एथलीटों ने 7.80 सेकंड के भीतर दौड़ पूरी की। स्विट्जरलैंड की डिटाजी कांबुंजी ने 7.73 सेकंड के साथ रजत और जमैका की अकेरा न्यूजेंट ने 7.74 सेकंड के साथ कांस्य पदक जीता। हालांकि, चीन की हर्डलर वू यान्नी फाइनल में नहीं पहुंच सकीं, लेकिन उन्होंने सेमीफाइनल में 8.01 सेकंड का समय निकालकर 11 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा।

अमेरिका की 4×400 मीटर रिले में शानदार जीत

पुरुषों की 4×400 मीटर रिले में अमेरिका ने 3:03.13 मिनट में स्वर्ण जीता। क्रिस बेली, ब्रायन फॉस्ट, जैकोरी पैटरसन और एलिजा गॉडविन की टीम ने जमैका को लगभग दो सेकंड के अंतर से हराया। हंगरी के एटिला मोलनार ने अंतिम दौर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए 3:06.03 मिनट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर कांस्य जीता। चीन ने भी 3:06.90 मिनट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया लेकिन चौथे स्थान पर रहा। महिला 4×400 मीटर रिले में अमेरिका की क्वानेरा हेस, बेली लीयर, रोजी एफियॉन्ग और एलेक्सिस होम्स की टीम ने 3:27.45 मिनट में स्वर्ण अपने नाम किया। पोलैंड ने 3:32.05 मिनट में रजत और ऑस्ट्रेलिया ने 3:32.65 मिनट में कांस्य पदक जीता।

अन्य प्रमुख मुकाबले

पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में अमेरिका के जोश होए ने 1:44.77 मिनट में स्वर्ण जीता, जबकि बेल्जियम के इलियट क्रेस्टन और स्पेन के एल्विन कनालेस क्रमश: रजत और कांस्य पदक हासिल किया। महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में दक्षिण अफ्रीका की प्रूडेंस सेकोडिसो ने 1:58.40 मिनट का विश्वस्तरीय व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर स्वर्ण जीता।

इथियोपिया की निगिस्ट गेटाच्यू और पुर्तगाल की पैट्रिसिया सिल्वा ने क्रमश: रजत और कांस्य पदक प्राप्त किया। 1500 मीटर पुरुष स्पर्धा में नॉर्वे के स्टार जैकब इंगेब्रिग्त्सेन ने 3:38.79 मिनट में स्वर्ण पदक जीतते हुए 3000 मीटर के बाद अपनी दूसरी खिताबी जीत दर्ज की।

ब्रिटेन के नील गॉर्ले ने रजत और अमेरिका के ल्यूक हॉउसर ने कांस्य जीता। 1500 मीटर महिलाओं की दौड़ में इथियोपिया की गुडाफ त्सेगाय ने 3:54.86 मिनट का चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण जीता, जबकि उनकी हमवतन दीरिबे वेलतेजी ने 3:59.30 मिनट में रजत पदक जीता। ब्रिटेन की जॉर्जिया हंटर बेल ने 3:59.84 मिनट में कांस्य पदक हासिल किया।

लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉट पुट में शानदार प्रदर्शन

इटली के मैटिया फुरलानी ने लॉन्ग जंप में 8.30 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि जमैका के वेन पिन्नॉक (8.29 मीटर) ने रजत और ऑस्ट्रेलिया के लियाम ऐडकॉक (8.28 मीटर) ने कांस्य पदक हासिल किया। अमेरिका की क्लेयर ब्रायंट ने महिला लॉन्ग जंप में 6.96 मीटर की व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर स्वर्ण अपने नाम किया। स्विट्जरलैंड की अनिक कालिन ने रजत और स्पेन की फातिमा दियामे ने कांस्य पदक जीता। महिला हाई जंप में ऑस्ट्रेलिया की निकोला ओलिस्लागर्स ने 1.97 मीटर की छलांग के साथ अपने खिताब का बचाव किया। उनकी हमवतन एलेनॉर पैटरसन ने रजत और यूक्रेन की यारोस्लावा महुचिख ने कांस्य पदक जीता। पुरुषों के शॉट पुट में न्यूजीलैंड के टॉम वॉल्श ने 21.65 मीटर के सीजन बेस्ट प्रदर्शन के साथ अपना तीसरा इंडोर खिताब जीता। स्वीडन के रोजर स्टीन ने रजत और अमेरिका के एड्रियन पाइपेरी ने कांस्य पदक हासिल किया।

हेप्टाथलॉन में नॉर्वे की शानदार जीत

नॉर्वे के सांडर स्कोटहेम ने हेप्टाथलॉन स्पर्धा में 6,475 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। यह उपलब्धि उन्होंने यूरोपीय इंडोर खिताब जीतने के कुछ ही हफ्तों बाद हासिल की। एस्टोनिया के जोहान्स एर्म (6,437 अंक) ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर रजत और जर्मनी के टिल स्टेनफोर्थ (6,275 अंक) ने कांस्य पदक हासिल किया।

चैंपियनशिप का समापन

2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप का समापन रोमांचक मुकाबलों के साथ हुआ, जिसमें अमेरिका ने कुल 16 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहते हुए अपना दबदबा कायम रखा।

खेलो इंडिया पैरा गेम्स की व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर की, खिलाड़ियों ने की सराहना

नई दिल्ली

खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 राष्ट्रीय स्तर पर पैरा एथलीटों के लिए एक बड़ा मंच बनकर उभरा है। इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे खिलाड़ियों ने इसकी व्यवस्थाओं की जमकर सराहना की है। इस साल छह खेल विधाओं में 1300 से अधिक पैरा एथलीटों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई है। रविवार को टूर्नामेंट के चौथे दिन तक पांच खेलों में 132 पदक तय हो चुके थे, जिसमें कई रोमांचक मुकाबले, अप्रत्याशित परिणाम और नए सितारों का उदय देखने को मिला। स्वयम जो इस टूर्नामेंट के एक्सेसिबिलिटी पार्टनर हैं, ने सभी स्टेडियमों, होटलों, हॉस्टलों और पार्किंग सुविधाओं का ऑडिट किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बाधा-मुक्त और पैरा खिलाड़ियों के अनुकूल हों। तमिलनाडु के रमेश शन्मुगम, जिन्होंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में तीन पदक जीते हैं, उन्होंने सरकार द्वारा कराई गई व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, यह प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के लिए एक शानदार मंच है। यहां की व्यवस्थाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर की हैं। हमें यात्रा और आवास की बेहतरीन सुविधाएं दी गई हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि टूर्नामेंट को लाइव स्ट्रीमिंग और मीडिया कवरेज मिल रही है, जिससे खिलाड़ियों को पहचान मिल रही है और यह उन्हें आगे बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर रही है। पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले संजीव कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की सराहना की। उन्होंने कहा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में खेलना गर्व की बात है। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने पूरे भारत में पैरा खेलों के लिए शानदार माहौल तैयार किया है। अब हमारे खिलाड़ी बड़े मंच पर खेल रहे हैं और पदक जीत रहे हैं। इसके अलावा मैं खेल प्राधिकरण का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पैरा एथलीटों को आगे बढ़ने के अवसर दिए हैं। दिल्ली पैरा पावरलिफ्टिंग टीम के कोच पवन ने कहा, सभी सुविधाएं पैरा खेलों के नियमानुसार दी गई हैं। खिलाड़ियों को न केवल स्पोर्ट्स किट और गाइड्स मिले हैं, बल्कि उनके साथ मौजूद सहायक को भी सुविधाएं दी जा रही हैं। बसों में रैंप, एसी और लो-फ्लोर की व्यवस्था की गई है। राजस्थान पैरा शूटिंग टीम की फिजियो डॉ. मुस्कान ने कहा, यहां हर चीज बेहतरीन है। होटल में शानदार सुविधाएं दी गई हैं।

राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग : फाइनल फेज के पांचवें दिन ओडिशा, मिजोरम, महाराष्ट्र और झारखंड की शानदार जीत

मारंग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम (रांची) में खेले जा रहे नेशनल विमेंस हॉकी लीग 2024-25 के फाइनल फेज के पांचवें दिन हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा, हॉकी मिजोरम, हॉकी महाराष्ट्र और हॉकी झारखंड ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर अंकतालिका में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। पहला मुकाबला हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने पूल-ए के मुकाबले में हॉकी हरियाणा को 2-0 से हराया। ओडिशा की ओर से प्रतिभा किंडो (9) और शिबानी लुगुन (59) ने गोल दागकर टीम को शानदार जीत दिलाई। इस जीत के साथ ओडिशा की टीम अंकतालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई, जबकि हॉकी हरियाणा अभी भी शीर्ष पर बनी हुई है। दूसरा मुकाबला हॉकी मिजोरम ने रोमांचक मुकाबले में हॉकी मध्य प्रदेश को 2-1 से हराकर तीसरे स्थान पर कब्जा जमाया। मिजोरम की ओर से लालतलछुंगी (42) और मंगलावमसंग (58) ने गोल किए, जबकि मध्य प्रदेश के लिए सुनीता कुमारी (54) ने एकमात्र गोल किया।

बांग्लादेश टीम के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को मैच के दौरान पड़ा दिल का दौरा, अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को सोमवार को ढाका प्रीमियर लीग (डीपीएल) के एक मुकाबले के दौरान दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।

36 वर्षीय तमीम इकबाल मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब की ओर से शाइनपुकुर क्रिकेट क्लब के खिलाफ बीकेएसपी मैदान में खेले जा रहे मैच में टीम की अगुवाई कर रहे थे, जब उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। मैदान पर ही उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के मुख्य चिकित्सक देबाशीष चौधरी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा, तमीम ने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी जांच की गई और ईसीजी किया गया। रिपोर्ट में थोड़ी समस्या पाई गई, लेकिन इस तरह की स्थिति में तुरंत कुछ समझ पाना मुश्किल होता है।

पहली ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में भी कुछ असामान्यताएं देखी गईं। हालांकि, तमीम को जब थोड़ी राहत महसूस हुई, तो उन्होंने ढाका वापस लौटने की इच्छा जताई लेकिन जैसे ही वह अस्पताल से निकलकर मैदान की ओर लौट रहे थे, उन्हें फिर से सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें फिर से अस्पताल ले जाया गया।

डॉक्टरों के अनुसार, इस बार तमीम को गंभीर हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें फजलतुननेस्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह अब डॉक्टरों की निगरानी में हैं।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तमीम इकबाल की सर्जरी की जा रही है और उनके हृदय की धमनियों में स्टेंट (एक विशेष प्रकार की जालीदार ट्यूब) डाला जाएगा, जिससे रक्त संचार सुचारू रूप से जारी रह सके।

इस घटना के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के कई निदेशक सावर पहुंच रहे हैं और इस वजह से बोर्ड की निर्धारित बैठक को सोमवार के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है।

पुर्तगाल ने डेनमार्क को हराकर नेशंस लीग सेमीफाइनल में बनाई जगह

लिस्बन

पुर्तगाल के फ्रांसिस्को ट्रिनकाओ ने बेंच से उतरकर दो गोल किए, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी शानदार प्रदर्शन किया, जिससे पुर्तगाल ने रविवार को अतिरिक्त समय में डेनमार्क को 5-2 से हराकर कुल 5-3 के अंतर से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ पुर्तगाल ने यूईएफए नेशंस लीग के सेमीफाइनल में जगह बना ली, जहां उसका मुकाबला जर्मनी से होगा।

रोनाल्डो की अगुवाई में मिली जीत रोनाल्डो ने भले ही शुरुआती पेनल्टी मिस कर दी हो, लेकिन उन्होंने अपनी टीम की वापसी में अहम भूमिका निभाई। हालांकि, उन्हें अतिरिक्त समय में बेंच पर बैठना पड़ा, फिर भी उन्होंने दर्शकों को लगातार उत्साहित किया और पुर्तगाल ने आखिरकार डेनमार्क की मजबूत रक्षात्मक पंक्ति को भेदने में सफलता पाई।

पहले चरण में डेनमार्क ने कोपेनहेगन में हुए मुकाबले में रासमस होजलुंड के गोल की बदौलत 1-0 की बढ़त बनाई थी। वहीं, डेनमार्क के मुख्य डिफेंडर जोआकिम माएले के कैंप छोड़ने से टीम को झटका लगा, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे के जन्म के लिए जाना पड़ा। उनकी जगह खेलने आए पैट्रिक डोर्गु ने शुरुआत में ही पुर्तगाल को पेनल्टी दे दी, जब उन्होंने रोनाल्डो को तीसरे मिनट में बॉक्स में गिरा दिया।

शुरुआती संघर्ष और पुर्तगाल की वापसी रोनाल्डो ने खुद पेनल्टी ली, लेकिन डेनमार्क के गोलकीपर कैस्पर श्माइकल ने शानदार बचाव कर उन्हें गोल करने से रोक दिया। इसके बाद 17वें मिनट में भी रोनाल्डो को नूनो मेंडेस के शानदार क्रॉस पर हेडर लगाने का मौका मिला, लेकिन श्माइकल ने फिर से उन्हें निराश कर दिया।

हालांकि, पुर्तगाल को 38वें मिनट में बढ़त मिल गई जब डेनमार्क के डिफेंडर जोआकिम एंडरसन ने गलती से गेंद को अपने ही गोल में डाल दिया। लेकिन 56वें मिनट में डेनमार्क के रासमस क्रिस्टेंसन ने कॉर्नर पर हेडर से गोल कर स्कोर बराबर कर दिया।

ट्रिनकाओ बने नायक इसके बाद रोनाल्डो ने 67वें मिनट में शानदार एंगल से गोल कर पुर्तगाल को फिर से बढ़त दिलाई, लेकिन 76वें मिनट में क्रिश्चियन एरिक्सन ने गोल कर डेनमार्क को फिर से कुल स्कोर में आगे कर दिया।

यहीं से फ्रांसिस्को ट्रिनकाओ ने खेल की दिशा बदल दी। उन्होंने 86वें मिनट में गोल कर स्कोर 3-3 किया और मुकाबला अतिरिक्त समय में चला गया। इसके बाद 91वें मिनट में ट्रिनकाओ ने एक शानदार चिप शॉट के जरिए गोल कर पुर्तगाल को बढ़त दिला दी। डेनमार्क ने आखिरी समय तक जमकर संघर्ष किया, लेकिन ट्रिनकाओ के दूसरे गोल के बाद उसकी ऊर्जा खत्म हो गई। इसके बाद पुर्तगाल के स्थानापन्न खिलाड़ी गोंसालो रामोस ने एक और गोल कर पुर्तगाल की जीत को और भी भव्य बना दिया। अब सेमीफाइनल में पुर्तगाल का मुकाबला जर्मनी से होगा, जिसने इटली को 5-4 के कुल स्कोर से हराया।

डरावनी राइड्स का मजा...

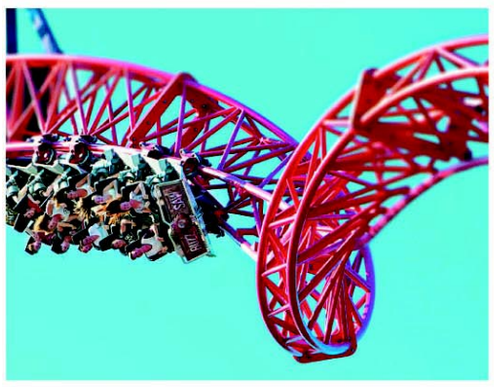

आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी डरावनी राइड्स के बारे में बताएंगे, जिनमें आप इन राइड्स का मजा पलक झपकते ही कुछ सेकंडों में ले सकते हैं। दुनिया भर में मशहूर इन राइड्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया हैं। तो आइए जानते हैं यह राइड्स किन-किन देशों में हैं और कितनी डरावनी हैं।

एक्स 2 सिक्स

लांस एंजेल्स का राइड एक्स 2 सिक्स फ्लैग्स मैगिक माउंटेन बिल्कुल 4डी राइड जैसा ही है। इसकी सीटें आगे-पीछे होती है और खुद ही घूमती जाती हैं।

फॉर्मूला रोशा

आबू-धाबी में बनी फॉर्मूला रोशा राइड दुनिया के सबसे तेज रोलर कोस्टर में शामिल है। इसकी स्पीड 240 किमी/घंटा होती है जिसके कारण इसकी 1 राइड लेने के लिए सिर्फ 5 सेकेंड लगते हैं। इस राइड को लेने के लिए चश्मे और हेलमेट लेकर ही इसमें बैठा जा सकता है।

टावर ऑफ टेरर

ऑस्ट्रेलिया में 100 फीट की ऊंचाई पर बना हैं टावर ऑफ टेरर। इस राइड की स्पीड 161 किमी/घंटे होने की वजह से नीचे आने के लिए सिर्फ 7 सेकेंड लगते हैं। लोग इसकी राइड लेते समय बहुत ज्यादा चीखते-चिल्लाते हैं।

लीप ऑफ फेथ

बहामास में बने इस लीप ऑफ फेथ में स्वीमिंग करने के लिए एक ट्यूब में नीले रंग का पानी और आसपास शॉर्क देखने को मिलती है। इस ट्यूब में स्वीमिंग करते हुए इन शॉर्क को देखने पर डर लगता हैं।

स्कैड टावर

डेनमार्क में बनी 100 फीट की ऊंचाई पर इस राइड को लेना बहुत ही डरावना हो सकता हैं। इस राइड के नीचे आने की स्पीड 88 किमी/घंटा हैं। इस राइड के नीचे डर को थोड़ा कम करने के लिए नेट लगाया गया है।

फॉरेनहाइट एट हर्शेपार्क

पेनसिलवेनिया 121 फीट ऊंचाई से इस फॉरेनहाइट एट हर्शेपार्क राइड लेते समय 97 डिग्री नीचे तक आया जाता है। इसे लेने के लिए सिर्फ 1 मिनट और उससे भी कम वक्त लगता है।

इनसैनिटी अटॉप

लॉस वेगास में इनसैनिटी अटॉप द स्ट्रैटोस्फीयर टावर राइड को लेने के लिए आपको 900 फीट की ऊचाई पर एक मैकेनिकल सीट पर बैठना होता है। इस राइड को लेने से आपको हवा में लटकने जैसा अहसास होता है।

घर की खुशबू...

घर की सुगंध से वहां रहने वालों के रिश्तों, व्यवहार, स्वभाव, आदतों व कलात्मक अभिरुचियों का पता चलता है। शोधों से पता चलता है कि खुशबू का व्यक्ति के व्यवहार व भावनाओं से सीधा संबंध है। सही खुशबू का चयन न सिर्फ डेकोरेशन के लिए जरूरी है, बल्कि इससे मन में सुकून भी रहता है।

इंसान के मन से सुगंध का नाता बडा पुराना है। कभी कोई सुगंध एकाएक अतीत में पहुंचा कर नॉस्टेल्जिक बना देती है, तो कोई मन में आशा-उत्साह का संचार करती है। जिस तरह मन व शरीर की सेहत के लिए अरोमाथेरेपी की जरूरत है, उसी तरह घर की सेहत के लिए भी यह जरूरी है। घर की सुगंध से वहां रहने वालों के रिश्तों, व्यवहार, स्वभाव, आदतों व कलात्मक अभिरुचियों का पता चलता है। शोधों से पता चलता है कि खुशबू का व्यक्ति के व्यवहार व भावनाओं से सीधा संबंध है। सही खुशबू का चयन न सिर्फ डेकोरेशन के लिए जरूरी है, बल्कि इससे मन में सुकून भी रहता है। पहले हर घर में सुबह-शाम अगरबत्तियां जलाई जाती थीं या ताजे फूल सजाए जाते थे। मगर अब घर को सुगंधित रखने के कई तरीके हैं। सारे एसेंशियल ऑयल या फ्रेग्रेंस परफ्यूम पर आधारित हैं। 100 फीसद शुद्ध खुशबू मिलना मुश्किल है, क्योंकि बाजार में एक किलोग्राम जैस्मिन का मूल्य करीब एक लाख रुपए है। लिहाजा एसेंशियल ऑयल में नॉन-टॉक्सिक अरोमा मिलाकर एक कॉम्बो तैयार किया जाता है, जिसमें इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं, ताकि फ्रेग्रेंस में कोईटॉक्सिक तत्व न मिलाया जा सके। रीड डिफ्यूजर्स, फ्रेग्रेंस वेपोराइजर्स और पोपोरीज भी मेंटेनेंस-फ्री अरोमेटिक अनुभव देते हैं।

कैंडल्स का जादू

अरोमा कैंडल्स बहुत लोकप्रिय हैं। इनसे कमरे को सॉफ्ट, रोमैंटिक माहौल मिलता है। डेकोरेशन और लाइट के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। मगर कैंडल्स लेने से पहले इनके इंग्रीडिएंट्स, साइज व शेप पर भी ध्यान देना चाहिए। पैराफिन वैक्स कैंडल्स सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। मगर ये जल्दी खत्म हो जाती हैं, जबकि बीज्वैक्स कैंडल्स देर तक जलती हैं। ये पैराफिन से महंगी होती हैं। माना जाता है कि ये एलर्जी की प्रॉब्लम में भी फायेदमंद है। पिलर कैंडल्स कॉमन हैं, जिन्हें होल्डर्स में फिट किया जा सकता है। ये अलग-अलग हाइट, कलर्स व खुशबू में मिलती हैं। कैंडल स्टिक्स प्रचलित हैं, लेकिन इन्हें होल्डर में नहीं लगाया जा सकता। टी लाइट्स छोटी होती हैं। इन्हें डेकोरेटिव कैंडल्स, फूड वार्मर्स या वोटिव होल्डर्स में इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोटिंग कैंडल्स को पानी से भरे कंटेनर्स में रखा जाता है। फिल्ड कैंडल्स सरैमिक कंटेनर या हीट रेजिस्टेंट ग्लास में रखी जा सकती हैं।

किड्स रूम की खुशबू बच्चों के बेडरूम या स्टडी में लेमनग्रास जरूरी है। इससे बने एसेंशियल ऑयल की एक बूंद भी कीटाणुओं से लडने में कारगर है। इसकी खुशबू एकाग्रता बढाती है। परीक्षा के दौरान इसका इस्तेमाल करें। रीड डिफ्यूजर या सरैमिक पॉट में इसकी एक-दो बूंद डालें और उसमें बैंबू स्टिक्स रखें। यह कॉम्बो किड्स रूम के लिए बेस्ट है।

खुशबू का चुनाव

घर में हर कमरे का अलग महत्व है। इसी के हिसाब से खुशबू चुननी चाहिए। बिना सोचे-समझे फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल से समस्याएं हो सकती हैं। लिविंग रूम वह कॉमन एरिया है, जहां पूरा परिवार एक साथ बैठता है या मेहमानों का स्वागत करता है। यहां सिट्रस, टीकवुड, एपल, सिनमन, लाइट फ्लोरल अरोमा इस्तेमाल करें। हेवी फ्रेग्रेंस यहां अच्छी नहीं लगती। छुट्टियों में पाइन या होली सेंट्स सही हैं। कैंडल्स लेने से पहले देखें कि क्या ये लिविंग रूम की कलर स्कीम से मैच करते हैं। बेडरूम में दिन भर की थकान के बाद व्यक्ति चैन की नींद लेना चाहता है। यहां शांत-सौम्य गंध अच्छी लगती है। अरोमाथेरेपी सेंट्स माहौल को रोमैंटिक भी बनाते हैं। लैवेंडर, सिनमन, जैस्मिन, क्यूकंबर, मेलन, ऑरेंज ब्लॉसम, लाइट रोज और पचोली जैसी सुगंध यहां अच्छी लगती हैं। लैवेंडर व वनीला से अच्छी नींद आती है तो यूकेलिप्टस या मिंट की सुगंध दबाव व थकान को दूर करती है। स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल यहां न करें।

किचन और डाइनिंग रूम

किचन में फूड सेंटेड कैंडल्स सही विकल्प हैं। वनीला, एपल, कॉफी, कुकी फ्लेवर्ड या सिट्रस फ्रेग्रेंसेज का चयन कर सकते हैं। पंपकिन, जिंजरब्रेड और सिनमन भी सही विकल्प हैं। पचोली, तुलसी या बेसिल भी विषैले तत्वों को डिटॉक्सीफाई करने में कारगर है। डाइनिंग रूम में फ्लोरल और फूड सेंट्स प्रयोग न करें। स्ट्रॉन्ग गंध खाने के स्वाद को प्रभावित कर सकती है। फ्रूटी फ्रेग्रेंसेज जैसे क्यूकंबर और व्हाइट सिट्रस किचन और डाइनिंग रूम के लिए सही हैं। बाथरूम के लिए लिनेन, सिट्रस, मिंट या ओशन थीम वाली खुशबू अच्छी लगती हैं। यहां व्हाइट, ब्ल्यू या बेज कलर्स की कैंडल्स अच्छी लगेंगी। डिफ्यूजर्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

फ्रेग्रेंस का मन से रिश्ता

लैवेंडर: शांति, संतुलन, सुकून देती है इसकी खुशबू। इससे तनाव, थकान, चिडचिडाहट, कुंठाएं, नर्वस एंग्जायटी, पैनिक हिस्टीरिया एवं इन्सोम्निया की समस्याएं दूर होती हैं।

सिनमन और जैस्मिन: यह फ्रेग्रेंस मन में सपने, इच्छाएं और आशा जगाती है। इसके अलावा व्यक्ति का आत्मविश्वास बढाने में भी कारगर है।

क्यूकंबर-मेलन: क्यूकंबर और मेलन का यूनीक कॉम्बो स्त्रियों की सेंसुअलिटी को बढाने में कारगर है। यह मन में रोमैंटिक भावनाओं का संचार भी करता है, साथ ही मसल्स को राहत देता है और तनाव व दबाव से उबारता है।

ऑरेंज ब्लॉसम और पचोली: टैंजरीन व पचोली की खुशबू आत्मविश्वास बढाने और मन में आशा का संचार करने में कारगर मानी जाती है। इससे तनाव-दबाव सहित पाचन तंत्र से जुडी समस्याएं भी दूर होती हैं।

प्राकृतिक तरीके

हाउसप्लांट्स में निवेश करें: अपने किचनगार्डन, बैलकनी या लॉन में कुछ फूल-पौधे या हर्ब्स अवश्य लगाएं ताकि इनकी महक घर को सुगंधित कर दे। किचन, बाथरूम, लिविंग रूम में भी हर्ब्स या छोटे पॉट्स रखे जा सकते हैं। हरे-भरे पौधे वायु प्रदूषण को भी कम करते हैं।

किचन को बनाएं खुशबू की लेबोरेट्री: संतरे के छिलके, नीबू या कोई भी सिट्रस फ्रूट्स किचन और फ्रिज को महका सकते हैं। गर्म पानी से भरे एक छोटे बोल में इन छिलकों को रखें तो किचन में फ्रेश सेंट महकेगा। बचे हुए छिलकों को बेकार न होने दें। इन्हें गर्म पानी में थोडे से डिटर्जेंट के साथ मिलाएं और इस मिश्रण से किचन यूटेंसिल्स या प्लैटफॉर्म की सफाई करें। सफाई बेहतर होगी तो बैक्टीरिया बेअसर होंगे और मन में भरेगा ताजगी भरा एहसास।

व्हाइट वेनेगर: कमरे के एक कोने में व्हाइट वेनेगर (सिरका) से भरे बोल रखें। दुर्गंध हटाने का यह प्राकृतिक तरीका है। घर के अलग-अलग हिस्सों को अलग खुशबू दें। लिविंग रूम के लिए लैवेंडर, बेडरूम में सेंडलवुड या बाथरूम में पैपरमिंट का इस्तेमाल करके देखें।

दूरियां मिटाते ब्रिज...

इस विशाल दुनिया को अगर कोई चीज एक करती है तो वह है नदी, सागर पर बने पुल। इनमें से अनेक अपनी खूबसूरती, ऊंचाई और लंबाई के लिए मशहूर हैं। हमेशा से पुलों का खासा महत्व रहा है, क्योंकि इनके बिना जमीनी परिवहन संभव ही नहीं। लोगों, संस्कृतियों को एक-दूसरे के करीब लाते पुलों पर एक नजर।

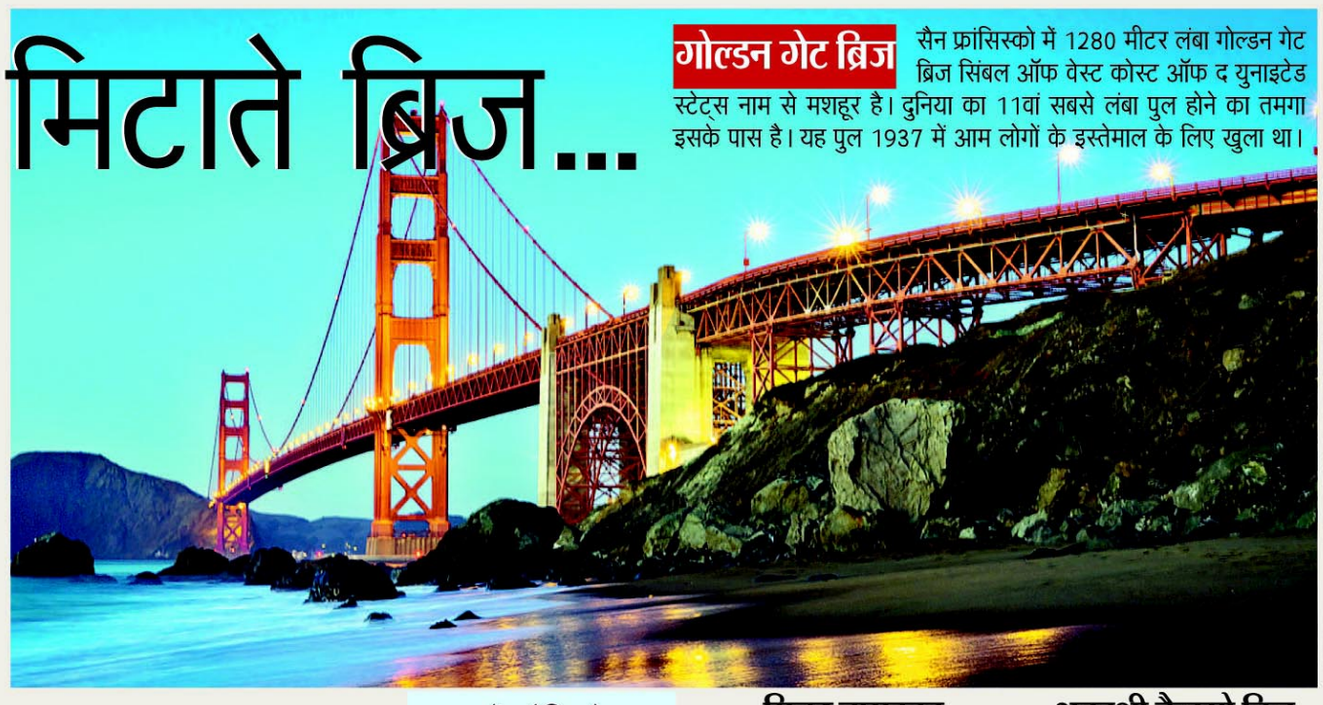

गोल्डन गेट ब्रिज

सैन फ्रांसिस्को में 1280 मीटर लंबा गोल्डन गेट ब्रिज सिंबल ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ द युनाइटेड स्टेट्स नाम से मशहूर है। दुनिया का 11वां सबसे लंबा पुल होने का तमगा इसके पास है। यह पुल 1937 में आम लोगों के इस्तेमाल के लिए खुला था।

टॉवर ब्रिज

लंदन में टॉवर ब्रिज 1886 में बनना शुरू हुआ और 1894 में बनकर तैयार हो गया। यह टेम्स नदी पर बना है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा पर्यटकों को अपनी ओर खींचने वाला पुल है।

ब्रूकलिन ब्रिज

न्यूयॉर्क में ब्रूकलिन ब्रिज 1883 में बनकर तैयार हुआ। यह अमेरिका के सबसे पुराने सस्पेंशन ब्रिज में से है। ब्रूकलिन ब्रिज न्यूयॉर्क में पर्यटकों के लिए हमेशा से खासी दिलचस्पी का केंद्र रहा है।

सिडनी हार्बर ब्रिज

ऑस्ट्रेलिया का सिडनी हार्बर ब्रिज अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। इस पुल पर हर नए साल पर होने वाली आतिशबाजी बेहद खास होती है।

पोंट वेक्कियो

इटली में पत्थर से बना पोंट वेक्कियो ब्रिज इकलौता ऐसा पुल है, जो द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका से बचा रहा। इस पुल पर दुकानें भी हैं। खास तौर पर ऑर्ट और ज्वैलरी की।

रिअल्टो ब्रिज

इटली के वेनिश शहर के 4 सबसे बड़े और पुराने पुलों में से एक है रिअल्टो ब्रिज। यह साल 1591 में बनकर तैयार हुआ, जिसने 1524 में तबाह हुए लकड़ी के पुल का स्थान लिया।

मिल्लउ वायडक्ट

फ्रांस में 343 मीटर ऊंचा मिल्लउ वायडक्ट ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। यह 2004 में बनकर तैयार हुआ, जो दक्षिणी फ्रांस में है। यह पुल एफिल टॉवर से भी ऊंचा है।

चार्ल्स ब्रिज

प्रॉग में व्लातवा नदी पर बना यह पुल 1357 ईस्वी में बनना शुरू हुआ और 15वीं शताब्दी की शुरुआत में जाकर बना। यह पुल पुराने प्रॉग शहर को तटीय क्षेत्र से जोड़ता है।

अकाशी कैक्यो ब्रिज

जापान में अकाशी कैक्यो ब्रिज1991 मीटर लंबा है, जो 1998 में बनकर तैयार हुआ। यह दुनिया का चौथा लंबा पुल है।

ग्रेट बेल्ड ब्रिज

डेनमार्क में ग्रेट बेल्ड ब्रिज1998 में बनकर तैयार हुआ। यह डेनिश आईलैंड ऑफ जीलैंड और फुनेन को जोड़ता है। यह पुल 6790 मीटर लंबा और 154 मीटर ऊंचा है। यह दुनिया का 8वां सबसे लंबा ब्रिज है।

सफल फेंगशुई का आधार...

फेंगसुई ऊर्जा को संतुलित करने की पद्धति का नाम है। इनके संतुलन से ही फेंगशुई प्रभावकारी होता है। इस विधा में जल, लकड़ी, अग्नि, पृथ्वी और धातु की दिशा के अनुरूप व्यवस्था ही सफल फेंगशुई का निर्माण करती है। यही कारण है कि घर का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि सूरज की रोशनी घर में अवश्य आए। चीनी वास्तु फेंगशुई का इतिहास करीब तीन हजार वर्ष पुराना है। फेंगशुई का शाब्दिक अर्थ है हवा और पानी। यह विधा पांच तत्वों पर आधारित है- जल, लकड़ी, अग्नि, पृथ्वी और धातु। इस विधा में नाकारात्मक ऊर्जा यिन व साकारात्मक ऊर्जा यांग के नाम से जानी जाती है। ये परस्पर विरोधी ऊर्जाएं हैं, जो एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त ब्राह्मांड की ऊर्जा जिसे ची के नाम से जाना जाता है।

फेंगशुई, ब्राह्मंड की ऊर्जा तथा यिन व यांग। घर की ऊर्जा व दिशाओं के अनुरूप तत्वों को व्यवस्थित करना और घर में रसोई, मुख्य शयन कक्ष, बच्चों का शयनकक्ष, धन व बहुमूल्य वस्तुओं को रखने का कक्ष या अलमारी, पढ़ाई का कक्ष आदि की तत्वों व दिशाओं के अनुरूप व्यवस्था ही सफल फेंगशुई का आधार है। जो घड़ियां बंद हों, उन्हें या तो घर से हटा देना चाहिए या फिर चालू कर देना चाहिए। घर में झाड़ू का उपयोग करने के बाद उसे इस तरह रखना चाहिए कि किसी की इस पर नजर न जाए। फेंगशुई के अनुसार इसका संबंध घर के धन और संपत्ति से होता है। पूरे घर में कालीन बिछा देने से पॉजिटिव शक्तियां घर के अंदर नहीं रह पाती। शीशे को घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। बाथरूम के दरवाजे के ठीक सामने भी कोई शीशा नहीं होना चाहिए। घर में बच्चों को डर लगे तो पीले रंग का बल्ब लगाना चाहिए। घर का मुख्य द्वार अन्य दरवाजों की तुलना में बड़ा होना चाहिए। मुख्य गेट दो पल्लों का होना चाहिए। मुख्य द्वार के दोनों ओर खिड़कियां नहीं होने चाहिए, इससे घर के मालिक को आर्थिक परेशानी हो सकती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दूर करने के लिए चीनी बेम्बू का प्रयोग करें। भाग्य को चमकाने के लिए मकान या व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर पवन घंटियां तथा चीनी सिक्के लगाएं। कछुए को घर में रखना प्रगति व स्वास्थ्य की दृष्टि से शुभ होता है।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**